।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

● वर्ष-4 ● अंक-150 रायपुर, रविवार 02 फरवरी 2025 ● पृष्ठ-8 ● मूल्य-3 रु.

राजनीति का जनपक्षकार

विकसित भारत @ में 2047 की दिशा में

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक 'बही-खाता' शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिए शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का एलान

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का एलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

दलहन में आत्मनिर्भरता- इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नैफेड और एनसीसीएफ तीन तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी।

सब्जी, फल और पोषण- श्रीअन्न और फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर एक योजना शुरू की जाएगी।

बिहार में मखाना बोर्ड- बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए घोषणा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या एक करोड़ है और इनसे 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये स्स्स्थ 45 फीसदी निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी.

किसे क्या मिला

मंत्रालय/विभाग	बजट (रुपये में)	मंत्रालय/विभाग	बजट (रुपये में)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	1.37 लाख करोड़	जलशक्ति मंत्रालय	99,000 करोड़
परमाणु ऊर्जा विभाग	3,992 करोड़	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	32,000 करोड़
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1.61 लाख करोड़	कानून एवं न्याय मंत्रालय	5,850 करोड़
नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय	2,400 करोड़	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय	23,000 करोड़
कोयला मंत्रालय	501 करोड़	खनन मंत्रालय	3,000 करोड़
आयुष मंत्रालय	3,992 करोड़	अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय	3,350 करोड़
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	18,446 करोड़	नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	26,000 करोड़
दूरसंचार मंत्रालय	1.08 लाख करोड़	पंचायती राज मंत्रालय	1,185 करोड़
उपभोक्ता मंत्रालय	2.15 लाख करोड़	संसदीय कार्य मंत्रालय	66 करोड़
सहकारिता मंत्रालय	1,186 करोड़	कार्मिक मंत्रालय	2,708 करोड़
कॉरपोरेट मंत्रालय	11,561 करोड़	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	19,000 करोड़
संस्कृति मंत्रालय	3,360 करोड़	नियोजन मंत्रालय	1,000 करोड़
रक्षा मंत्रालय	6.81 लाख करोड़	बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय	3,470 करोड़
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय	5,915 करोड़	ऊर्जा मंत्रालय	21,000 करोड़
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,649 करोड़	रेल मंत्रालय	2.55 लाख करोड़
शिक्षा मंत्रालय	1.28 लाख करोड़	सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय	2.87 लाख करोड़
आईटी मंत्रालय	26,000 करोड़	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1.90 लाख करोड़
पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3,412 करोड़	विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय	38,000 करोड़
		कौशल विकास मंत्रालय	6,100 करोड़
विदेश मंत्रालय	20,000 करोड़	सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय	14,000 करोड़
वित्त मंत्रालय	19.3 लाख करोड़	अंतरिक्ष मंत्रालय	13,000 करोड़
मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	7,544 करोड़	सांख्यिकी मंत्रालय	5,400 करोड़
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4,364 करोड़	इस्पात मंत्रालय	3,362 करोड़
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	99,000 करोड़	टेक्सटाइल मंत्रालय	5,272 करोड़
भारी उद्योग मंत्रालय	7,680 करोड़	पर्यटन मंत्रालय	2,541 करोड़
गृह मंत्रालय	2.33 लाख करोड़	आदिवासी कल्याण मंत्रालय	14,000 करोड़
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय	96,000 करोड़	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	26,000 करोड़
सूचना प्रसारण मंत्रालय	4,358 करोड़	युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय	3,794 करोड़

टर्म लोन

पहली बार उद्यमी बनने वालों को दो करोड़ रुपये का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके दायरे में पांच लाख महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के दायरे में आएंगे।

कस्टमाइज्ड क्रेडिट

सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा पांच लाख रुपये होगी। पहले वर्ष ऐसे 1 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

इन पांच बिंदुओं पर आधारित है बजट 2025-26

- विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए
- समग्र विकास करने के लिए
- निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए
- घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए
- मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए

फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी

- फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए योजना पर अमल किया जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्लीन टेक विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा
- नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान करने के लिए
- लेदर फुटवियर और लेदर उत्पादों को भी समर्थन

महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये का टर्म लोन

- एससी, एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन होगा। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के साथ पहली बार उद्यमी बनने वाली एससी, एसटी महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

बजट से संबंधित शेष पृष्ठ 6 पर

प्रमुख समाचार

बजट में गरीबों के लिए सरकार का बड़ा एलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट में गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार एक करोड़ %गिग वर्कर्स% को मदद देने के लिए ई-श्रम मंच पर पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करेगी।

इसके लिए श्रमिकों के पहचान पत्र की व्यवस्था भी की जाएगी। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी गिग कर्मियों की श्रेणी में आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा, ऑनलाइन मंच के 'गिग वर्कर न्यू एज सर्विस अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। उनके योगदान को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ई-श्रम पोर्टल पर उनके पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है।

निवेश, उपभोग और विकास को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। मोदी ने इसे देश की आकांक्षाओं का बजट बताया है। मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत की विकास यात्रा में एक

महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। उन्होंने कहा कि यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं। विकसित भारत के मिशन को आम नागरिक चलाने वाला है। मोदी ने कहा कि यह बजट शक्ति बढ़ाने वाला है। यह बजट बचत, निवेश, उपभोग और विकास को बढ़ाएगा। मैं जन-केंद्रित बजट लाने के लिए निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे... ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।

बजट ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित : सीतारमण

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बजट उत्तरदायी सरकार को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री

मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर सरलीकरण जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे... इसलिए यदि हम कराधान को शामिल करते हुए सुधार की बात कर रहे हैं, तो काम पूरा हो चुका है। यह बजट युक्तिकरण और सीमा शुल्क के बारे में भी बात करता है। टैरिफ को कम किया जा रहा है, टैरिफ को सरल बनाया जा रहा है। बजट प्रस्तुति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है। हम सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव पर जोर देना जारी रखते हैं, जिसने हमें टिकाए रखा है। हम उस पर काम करना जारी रखते हैं, और इन सबके साथ, हमारी राजकोषीय समझदारी बनी हुई है।

मुठभेड़ में आठ माओवादी ढेर गोलीबारी अब भी जारी

बीजापुर । बीजापुर जिले के गंगालुर थाना क्षेत्र के तोड़का इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ आठ नक्सली मारे गए। सूत्रों के मुताबिक, मारे गए सभी नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के जवान शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से कई स्वचलित हथियार भी बरामद होने की खबर है। इससे पहले नक्सल प्रभावित जिला गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली थी। कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 14 नक्सली मारे गये थे। वहीं, सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट का एक जवान भी घायल हुआ था। 14 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर किए गए। मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने जहां आठ नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं घटना स्थल से जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ इंसास रायफल और बीजीएल लॉचर जैसे हथियार भी बरामद किये हैं। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में आठ से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं।वहीं कई नक्सली घायल भी हुए हैं। अभी भी इलाके में सर्चिंग जारी है।

भाजपा में शामिल हुए आप के आठ विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को केवल चार दिन शेष बचे हैं। 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राजधानी में बड़े-बड़े उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में जिन आठ विधायकों को शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था, वो सभी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि 24 घंटे पहले ही इन सभी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दिया था। इन सभी को आप से टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये सभी नाराज चल रहे थे। जबकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि इन विधायकों पर भाजपा और कांग्रेस ने दबाव बनाया है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले अधिकांश विधायकों के त्यागपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस्तीफा देने वाले कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल का कहना था कि उन्होंने छह अन्य विधायकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ से होंगे बड़े काम

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में वित्त मंत्री ने अपने बजट में एक बार भी भारतीय रेलवे का जिक्र तक नहीं किया है। हालांकि उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए वित्तीय वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़ का आवंटन किया है। ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025) के लिए आवंटित राशि के समान है। आम बजट में रेलवे को लेकर कोई नई घोषणा की बजाय पहले की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

दरअसल, वित्तमंत्री ने 2024 के आम बजट में रेलवे के लिए कुल बजटीय समर्थन 2,55,200 करोड़ रखा। यह वर्ष 2023-24 में 2,40,200 करोड़ से 5 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त वित्तमंत्री ने 10,000 करोड़ अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से आवंटित किए गए थे। जुलाई 2024 में वित्तमंत्री द्वारा पेश किए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की थी। साथ ही यह भी कहा था कि भारत में तीन प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारे बनेंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व

वाला गलियारा शामिल होगा।

रेलवे को बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें राजस्व में 3445 करोड़ रुपये और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2,52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह रेलवे बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में पेंशन फंड में 66 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। जबकि नई लाइनें बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लाइनों के दोहरीकरण में 32,000 करोड़ और गॉज लाइन में बदलने में 4,550 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

इसके अलावा आम बजट में रेलवे की सिग्नलिंग और टेलीकॉम के लिए 6800 करोड़, विद्युत लाइनों के लिए 6,150 करोड़ रुपये, स्टाफ कल्याण पर 833 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग उद्देश्य के लिए 301 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं रेलवे सेफ्टी फंड में 45 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। रेलवे मंत्रालय रेल हादसों को कम करने के लिए खास कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत देश के प्रमुख रेलवे रूट पर कचव का अपग्रेट वर्जन 4.ह्र लगाने का काम तेजी से किया जाएग। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में इसे लेकर कोई भी नई घोषणा नहीं की है। लेकिन बजट आवंटन में पूर्व की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है।

रेलवे में कैपेक्स पर आवंटन बढ़ाने की थी उम्मीद

रेलवे से जुड़े एक सूत्र के अनुसार आने वाले बजट में रेलवे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर आवंटन 20 फीसदी तक बढ़ाए जाने की उम्मीद थी। रेलवे के अनुमानों के अनुसार पिछले बजट में इस मद में मिले 2.65 लाख करोड़ रुपये में से रेलवे ने करीब 80 फीसदी खर्च कर लिए हैं। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

कुल बजट	2,55,445 करोड़
राजस्व खर्च	3,445 करोड़
पूंजीगत व्यय	2,52,000 करोड़
पेंशन फंड	66,000 करोड़
नई रेलवे लाइनें	32,235 करोड़
लाइन दोहरीकरण	32,000 करोड़
गॉज परिवर्तन	4,550 करोड़
सिग्नलिंग और टेलीकॉम	6,800 करोड़
विद्युत लाइनों का विस्तार	6,150 करोड़
स्टाफ कल्याण	833 करोड़
रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग	301 करोड़
रेलवे सेफ्टी फंड	45,000 करोड़

गाजे बाजे के साथ भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली

कोरिया। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोरिया के सभी जिला पंचायत सदस्यों और दो जनपद पंचायत बैकुंठपुर और सोनहत के जनपद सदस्यों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

31 जनवरी को जिला पंचायत कोरिया के 10 में से 9 भाजपा प्रत्याशियों ने बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। कोरिया जिले की दोनों जनपद पंचायत के भाजपा समर्थित, अधिकृत प्रत्याशियों ने अपने अपने जनपद मुख्यालय में सैकड़ों समर्थकों बीच बाजे गाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल किया।

भाजपा की नामांकन रैली में मुख्य रूप से शामिल बैकुंठपुर विधायक भइया लाल राजवाड़े ने कहा कि भाजपा से उतारे गए सभी प्रत्याशी लोकप्रिय हैं और सभी प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। राजवाड़े ने दावा किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय सरकार के विकास सहित मोदी की गारंटी के साथ चुनाव जीतेंगे। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी।

प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान विधायक भरतपुर सोनहत रेणुका सिंह ने कहा कि हमारे सभी प्रत्याशियों की क्षेत्र में और भाजपा में अच्छी और ईमानदार के साथ कर्मठ छवि है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकताओं की मेहनत और प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के विकास सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित की योजना जैसे महतारी वंदन के रूप में प्रदेश की बहनों को आर्थिक सहयोग, किसानों से

ऊंचे समर्थन मूल्य में उपज खरीदने और उन्हें अंतर की राशि के रूप में कृषि उन्नति के लिए लाभ प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आवास दिलाने सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से जीत मिलेगी। कोरिया जिले के युवा जिला अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा एकजुटता और हर अभियान पर जीत दर्ज करने की जिद और बुलंद हौसला ही हमारी जीत को तय कर देती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार देश में विकास और उन्नति की जननी मानी जाती है। जिनकी पहल से समूचे राष्ट्र और प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं की बयार चल रही है। प्रदेश की विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। उन्होंने दावा किया कि निश्चित ही हम निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में जोरदार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। नामांकन रैली में शामिल त्रिस्तरीय चुनाव प्रभारी कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रत्याशियों की साफ सुथरी छवि के साथ केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं और प्रदेश की विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार की वजह से त्रिस्तरीय चुनाव को जीत मिलेगी।

लोहारा नगर पंचायत में दिलचस्प लड़ाई

बालोद। बालोद जिले के डोंडिलोहारा नगर पंचायत में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि एक तरफ भाजपा ने राज घराने के युवराज लाल निवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के खेमे से अनिल लोढ़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी अब जोर आजमाइश में लग चुके हैं और जनसंपर्क भी जारी है।

भाजपा प्रत्याशी लाल निवेंद्र सिंह ने जहां पिछले 10 साल से कांग्रेस समर्थित अध्यक्षीय कार्यकाल को भ्रष्टाचार से भरा हुआ बताया तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल लोढ़ा ने कहा कि हमारे क्षेत्र में मंत्री ने ऐसे विकास कार्य कराए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए नगर का चहुमुखी विकास हुआ है।

कांग्रेस प्रत्याशी अनिला लोढ़ा ने बताया कि पूरे नगर पंचायत में हम घूम-घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और इस नगर में जो भी विकास कार्य जनता चाहती है। उसी के हिसाब से ही विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसी के अनुसार से हम कार्य योजना बनाएंगे। पार्टी ने हमें विश्वास के साथ मैदान में उतारा है तो हम विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

भाजपा के 1 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुए विकास कार्य : गुरु रुद्र कुमार

बेमेतरा। नगरीय निकाय के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का दौर भी बेमेतरा जिले में चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने शुक्रवार को जिला पंचायत बेमेतरा में नामांकन जमा किया। जहां भाजपा प्रत्याशियों के साथ नामांकन फार्म जमा करने किसान नेता योगेश तिवारी और कांग्रेसी प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी जिला पंचायत पहुंचे।

बेमेतरा जिला पंचायत में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने सालभर से ज्यादा हो गया है लेकिन प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुए है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था चरमाई हुई है। पूर्व मंत्री ने गिरौधपुरी और बलौदाबाजार की घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज और ओबीसी वर्ग को तोड़ने के लिए भाजपा सरकार लगी हुई है।

धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने को लेकर कुमार ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। कहा कि भाजपा दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। जनता के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही है। जबकि कांग्रेस सरकार सिर्फ जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल के इस्तीफा पर कहा कि पार्टी फोरम में यह बात रखी जाएगी।

बेमेतरा जिला भाजपा के किसान भाजपा नेता योगेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है। जिसके कारण आपसी खींचतान की वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण विकास के कार्य बाधित थे। योगेश तिवारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का साथ देकर उनके प्रत्याशियों को जिताए ताकि प्रदेश में विकास हो।

बस्तर में जल्द अमन, चैन और शांति का माहौल: सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सुरक्षाबल के जवानों को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया कि बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को लेकर कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से मिलेगी।

सीएम साय ने कहा कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने बेहतर जीवन और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो हिंसा का रास्ता छोड़ गणतंत्र का मार्ग अपनाते हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सुरक्षाबल के जवानों को बधाई दी है।

लगातार नक्सली कर रहे आत्मसमर्पण

उन्होंने बताया कि कांकेर जिले में 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले नारायणपुर जिले के 27 एवं सुकमा जिले के 52 लाख के ईनामी 9 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह हमारी सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण नीति और नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

नक्सली मुठभेड़ों में 265 का खात्मा

सीएम साय ने कहा कि अब तक 941 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1,112 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। नक्सली मुठभेड़ों में 265 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और बेहतर जीवन की उम्मीद में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

माओवादी विचारधारा छोड़कर बेहतर जीवन जी रहे

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं अपने बस्तर दौरे के दौरान अक्सर आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिलता हूं। उनसे बातचीत में यह साफ झलकता है कि खोखली माओवादी विचारधारा को छोड़कर वे आज बेहतर जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। घोर नक्सल प्रभावित जिलों के चिन्हित ग्रामों में नक्सल आधार को खत्म करने के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मूलभूत आवश्यकताओं का विकास कर रही है।

नक्सल पीड़ितों के लिए पीएम आवास स्वीकृत

सीएम साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। तय समय-सीमा के भीतर माओवाद के आतंक का अंत होगा। बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा।

किसान से मोबाइल लूटने वाले बिहार के दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। पाटन रोड ढौर चौक के पहले किसान का मोबाइल लूटने वाले बिहार के दो आरोपियों को उतई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल एवं लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

प्रार्थी त्रिभुवन साहू निवासी ग्राम ढौर में उतई थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। 29 जनवरी को वह सेलुद में वायसर लेने के लिए गया हुआ था। वहां से वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 07बी वी 9842 से वापस अपने घर ढौर लौट रहा था। दोपहर लगभग 2 बजे पाटन रोड ढौर चौक के पहले पहुंचा था कि अचानक मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 07 बी क्यू 7916 पर सवार होकर दो आरोपी आए और अपनी मोटरसाइकिल को प्रार्थी की मोटरसाइकिल में टिका दिए। इससे अनियंत्रित होकर प्रार्थी मोटरसाइकिल सहित रोड पर गिर गया। इसके बाद दोनों आरोपी प्रार्थी से बोले कि तुम्हारे पास जो भी सामान हो उसे हमें दे दो। प्रार्थी ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है, तो एक लड़के ने प्रार्थी के जेब में रखे 14000 रुपए कीमत के मोबाइल को लूट लिया और दोनों भी तेजी से ढौर गांव की ओर भाग निकले थे। घटना की जानकारी मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने लूट के आरोपियों को जल्द से जल्द पकडने के निर्देश दिए थे। उतई थाना प्रभारी विपिन रंगारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।

संदेह के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेही नीरज कुमार सरदार एवं रामरतन यादव जो कि गुरु कृपा फिड्स मिल ग्राम ढौर में काम करते और वही रहते हैं को पूछताछ में लिया। पूछताछ में नीरज कुमार सरदार एवं राम रतन कुमार यादव दोनों निवासी बिहार ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वह अपने ठेकेदार नीतीश यादव की मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 07 बी क्यू 7916 को मांग कर दुर्ग घूमने गए हुए थे। दोपहर में वह वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति मोटरसाइकिल से अकेले जा रहा था। सुनसान होने का फायदा उठाकर इन दोनों ने लूट की योजना बनाई और गाड़ी को ओवरटेक कर मोटरसाइकिल को रोका था।

गुणवत्ताहीन शिक्षा के मामले में शिक्षा सचिव ने की कार्रवाई

दो शिक्षकों को नोटिस, दो निलंबित

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव परदेशी ने गरियाबंद जिले का दौरा कर स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की स्थिति का जायजा लिया। शिक्षा सचिव ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारूका और मालगांव के निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 8वीं के छात्रों के अधिगम स्तर में भारी गिरावट और विद्यार्थियों की विषयगत समझ अत्यंत कमजोर पाए जाने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने इसके लिए शाला के प्रधान पाठक ललित कुमार साहू (बारूका) और संकुल समन्वयक भूपेन्द्र सिंह ठाकुर (मालगांव) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। जिसके परिपालन में संभागीय संयुक्त संचालक राकेश कुमार पाण्डेय ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।

शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारूका के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर परखने के लिए उनसे सहज सवाल पूछे। शिक्षा सचिव ने पाया कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान का स्तर अत्यंत कमजोर है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका दीपा साहू और कविता साहू से भी शिक्षा सचिव ने अध्ययन-अध्यापन को लेकर सवाल किए।

शाला में पदस्थ दोनों शिक्षिकाओं का शैक्षणिक स्तर संतोषजनक नहीं पाए, विद्यालय की साफ-सफाई और प्रबंधन की लचर स्थिति को लेकर शिक्षा सचिव ने नाराजगी जताई। शिक्षा सचिव के निर्देश पर दोनों शिक्षिकाओं को शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जबाब तलब किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी पर जानलेवा हमला

जगदलपुर। जगदलपुर में महापौर प्रत्याशी के रूप में आम आदमी पार्टी से खड़े हुए समीर खान के ऊपर बीती रात कुछ लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। घायल को बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया। जहां मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के साथ ही परिजन मौके पर आ पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए महापौर प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए समीर खान ने बताया कि रात को अपने काम को खत्म करके अपनी स्कूटी वाहन में सवार होकर घर जा रहे थे कि अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक से उसपर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें चोट भी आई। घटना की जानकारी 112 डायल को दी। जहां घायल को बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं, मामले की जांच शुरू कर दिया गया है।

भाभी ने देवर पर किया कुल्हाड़ी से हमला

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम केरा के भाटापारा में भाभी पुष्पा बंजारे और देवर राम खिलावन बंजारे के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया। जिससे लहू लुहान जमीन पर गिर गया। राम खिलावन बंजारे शराब के नशे में घर पहुंचा और बर्थडे पार्टी के बीच में उल्टी कर दी। जिसपर पुष्पा बंजारे ने नाराजगी जताई और दोनों के बीच विवाद हुआ था। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, शुकवार की रात करीबन 9 से 9.30 बजे के बीच पुष्पा बंजारे अपने घर में बर्थडे थी। इस दौरान देवर राम खिलावन बंजारे जोकि शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और बर्थडे पार्टी के बीच उल्टी करने लगा। जिसे देख पुष्पा बंजारे ने नाराजगी जताई तो देवर राम खिलावन ने गला दबा कर उसे मारने की कोशिश की। इस दौरान अपने बचाव में पुष्पा बंजारे ने पास में रखे कुल्हाड़ी से देवर राम खिलावन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे चोट लगने पर वहीं जमीन पर लहूलुहान गिर पड़ा। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची।

भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में जलकर राख हुआ गांजा

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए अभियान के तहत विभिन्न प्रकरण में जब्त किए गए 338.325 किलो (3 क्विंटल से अधिक) गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के निर्देशन में एसएमएस-3, भिलाई स्टील प्लांट की भट्टी में जलाकर विधिवत नष्ट किया गया। न्यायालय के आदेश पर इस नष्टीकरण प्रक्रिया में सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 60 नग नशीले इंजेक्शन भी नष्ट किए गए। इन सब की अनुमानित कीमत 79 लाख 82 हजार 258रुपए है। डीएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि रेंज के अन्य जिलों से संबंधित मादक पदार्थों को भी विधिवत नष्ट किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर निरंतर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस की दृढ़ इच्छाशक्ति व जिले को नशामुक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इस अभियान के तहत मादक पदार्थ के तस्करों व व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।

अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग कि कार्रवाई

बीजापुर। बीजापुर में आदर्श आचार संहिता के बीच आबकारी विभाग नें बड़ी कार्यवाही कि है। अवैध शराब पर नकेल कसते हुए बड़ी मात्रा में शराब कि बोतलें जप्त कि गई हैं।भोपालपटनम के रुद्रारम से 141 बल्क लीटर माल जप्त कर आबकारी विभाग ने कार्यवाही की है। बताया गया है कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना से शराब लाकर आरोपी पागे सत्यम, जंगम पिता समैया उम्र 37 यहां बेच रहा था। जिसमे 96 नग गुड डे व्हिस्की पाव (प्रत्येक 180 एमएल), 1 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की बोतल (750 एमएल), 18 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की अदद्दा (प्रत्येक 375 एमएल), 23 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की पाव(प्रत्येक 180 एमएल), 191 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की प्रत्येक 90 एमएल, 74 नग किंगफिशर बीयर प्रत्येक 650 एमएल, 39 नग नॉक आउट प्रत्येक बियर 650 एमएल, 33 नग हेवर्ड 5000 बीयर, जिसकी कुल कीमत 68160 हैं। रुद्रारम के रहने वाले आरोपी पागे सत्यम, पिता समैया, जंगम, उम्र-37 पर धारा 34 (2), 36, 59 (क) की कार्यवाही की गई हैं।

पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लटीया फाटक के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने साइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग राम कुमार श्रीवास 65 वर्ष को गंभीर चोट आने पर सीएचसी अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, पिकअप वाहन और चालक को पुलिस ने हिरासत में लिए है। घटना अकलतरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, खोड निवासी राम कुमार श्रीवास साइकिल से अपने घर आ रहे थे, लटिया फाटक के पहुंचते ही पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलते हुए पीछे से उन्हें टक्कर मार दी। राम कुमार श्रीवास दूर सड़क पर जा गिरे। वहीं, सायकल भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में राम कुमार श्रीवास को चोट आने पर गंभीर हालत में राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जहां डॉक्टर ने राम कुमार श्रीवास को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच मे जुटी है।

चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म में मिला बर्ड फ्लू का केस, मुर्गी और अंडों को किया गया नष्ट

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय के पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होनें के बाद देर रात जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने शासकीय पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों, चूजों के अलावा हजार अण्डो को नष्ट करने के बाद रायगढ़ शहर व आसपास के दस किलोमीटर क्षेत्र में मुर्गियों व अंडो की ब्रिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ पशु पालन विभाग, नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीम को पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर दायरे में सघन जांच अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होनें के बाद राजधानी रायपुर से भी चार सदस्यीय टीम रायगढ़ पहुंच गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधर नगर स्थित पोल्ट्री फार्म में कुछ दिन पहले ही कुछ मुर्गियों की मौत के बाद पशु पालन ने उसके सैंपल 28 जनवरी को लाइब्रेरी भेजे थे और इस सैंपल की जांच के बाद फारेसिक लैब की टीम ने मुर्गी की मौत में बर्ड फ्लू के कारण होना पाया गया जिसके चलते तत्काल जिला कलेक्टर ने देर रात बैठक लेते हुए चक्रधर नगर स्थित पोल्ट्री फार्म की समस्त मुर्गियों, चीजों तथा अंडो को नष्ट करने के आदेश दिये। साथ ही साथ भारत सरकार के एक्शन प्लान फार प्रिवेंशन कंट्रोल एण्ड कंटेनमेंट आफ एवियन इन्फ्लूएंजा रिवाइज्ड (2021) के तहत फोल्ट्री फार्म का एक किलोमीटर का क्षेत्र इंफेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर दायरे में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया गया है।

बर्ड फ्लू की पुष्टि होनें के बाद रायपुर से आये अधिकारियों की टीम ने इसके वायरल को खत्म करने के लिये जांच अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आवश्यक निर्देश के तहत अंडे एवं मुर्गियों का सेवन भी नही करने की सलाह दी है। अधिकारी ने बताया कि यह वायरल आम आदमी के लिये उतना खतरनाक नही है फिर भी बचाव के लिये सभी उपाये करने

चाहिए। नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी रात संयुक्त अभियान चलाकर संक्रामक रोग प्रोटोकॉल के तहत पोल्ट्री फार्म की सभी 05 हजार मुर्गी, 12 हजार चूजे, 17 हजार अंडे और कुक्कुट आहार को नष्ट किया। इसके लिए मुर्गों और चूजों को मारकर जमीन में दफनाया गया। इसके लिए पोल्ट्री फार्म परिसर में पूरे सुरक्षात्मक उपायों के साथ जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसमें नमक और चुने की लेयर बिछा कर मुर्गियों और चूजों को दफनाया गया और ऊपर से फिर नमक और चुने की लेयर डाली गई। इसी प्रकार अंडों को भी नष्ट किया गया। जिससे संक्रमण न फैले। इसके साथ ही परिसर को संक्रमण मुक्त करने डिसइनफेक्शन किया जा रहा है।

राजधानी रायपुर से आये राज्य पशुरोग अनुसंधान के डॉ. अनिल कुमार तपसी ने बताया कि मुख्य इंफेक्शन जो मुर्गियों में आया है उसकी पुष्टि हुई और उसे हमने रात में ही नष्ट कर दिया है। उसके बचे दाना, पुआल को नष्ट करने के अलावा 01 किलोमीटर के आसपास के मुर्गियों को नष्ट करने के बाद सर्वेलेंस का काम करना है। इस स्थित में मांस का सेवन बहुत कम करें और अगर करना ही है तो अच्छे से उबाल कर करें।

रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि कल रात भोपाल के लैब से रिपोर्ट आने के बाद रात 01 बजे से सुबह 06 तक मुर्गियों के अलावा अंडो और चूजो को नष्ट किया गया। चक्रधर नगर में स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र से लेकर एक किलोमीटर तक सारे पोल्ट्री पदार्थो को नष्ट कर दिया गया है। निजी लोगों का पोल्ट्री पदार्थ नष्ट किया जाता है उसमें उनको मुआवजा मिलता है। उसके रिकार्ड रखे गए है एक दो सप्ताह में उन्हें मुआवजा मिल जाएगा।

पक्षियों का उच्च पैंथोपनिक एवियन इन्फ्लूएंजा रोग पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगो का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 अंतर्गत अनुसूचित रोग है। जिसके रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ एवियन इन्फ्लूएंजा (रिवाइज्ड 2021) के अनुसार कार्यवाही की जानी होती है। परिपालन में शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ से एक किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सर्विलांस जोन घोषित किया गया है।

3 साल का बच्चा हुआ एचएमपीवी वायरस का शिकार

बिलासपुर। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस (एचएमपीवी) का पहला केस छत्तीसगढ़ में मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यहां तीन साल का बच्चा जो कोरबा का रहने वाला है और उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बालक की स्थिति स्थिर है लेकिन एचएमपीवी वायरस दूसरों को और न फैले इसके लिए कोरबा और बिलासपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है साथ ही लक्षण वाले मरीजों का सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

जब मध्यम वर्ग के पास अधिक धन बचेगा, तो वे अधिक खर्च और निवेश करेंगे : सीए किशोर

रायपुर। 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट एक ऐतिहासिक निर्णय है जो मध्यम वर्ग, समाज और देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी साबित होगा। यह करदाताओं के हाथ में अधिक धन सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी खपत, बचत और निवेश की शक्ति बढ़ेगी। आईसीएआई के पूर्व चेयरमेन सीए किशोर बरडिया ने कहा कि जब मध्यम वर्ग के पास अधिक धन बचेगा, तो वे अधिक खर्च और निवेश करेंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एमएसएमई को इस बढ़ी हुई मांग का लाभ मिलेगा। कर छूट से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। हालांकि सरकार को सीधे करों से कुछ नुकसान होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष कर और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से यह नुकसान पूरा हो जाएगा। डिजिटल इकॉनमी और कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी इससे मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कृषि विवि में स्थापित रिसर्च लैब का किया अवलोकन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका और

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित आर एच रिछारिया रिसर्च लैब का अवलोकन किया। राज्यपाल श्री डेका ने रिसर्च लैब के अवलोकन के दौरान इसके विभिन्न अनुभागों का भ्रमण किया और विद्यार्थियों व रिसर्च स्कॉलरों के साथ चर्चा की। उन्होंने लैब के माध्यम से कृषकों के कल्याण को समर्पित अनुसंधान कार्य और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने चावल के इंडीजिनस किस्मों के बारे में भी जाना और छत्तीसगढ़ में इसको बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा। उन्होंने क्रॉप बायोफार्टिफिकेशन लैब के अवलोकन के दौरान संजीवनी राइस, जिंको राइस, न्यूट्री रिच राइस जीनोटाइप सहित असम से लाए बम्बू टिश्यू कल्चर को लेकर किए जा रहे नए प्रयोगों को देखा। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और देश भर से आए प्रशिक्षु विद्यार्थियों से भी आत्मीय चर्चा की । इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल भी मौजूद रहे।

राईस मिलर्स एसो. के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगेश अग्रवाल लंबे समय से अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी सूचना एसोसिएशन को दे दी है। साथ ही पूरी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा भी की है। योगेश अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैंने और पूरी टीम ने सबकी सेवा करने अपनी पूरी ऊर्जा से काम किया। अब मैं अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता हूं और पूरी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने हम मिलर्स की सभी मांगों को मान भी लिया है। सरकार और अधिकारियों ने मुझे पूरा सहयोग दिया। इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि राइस मिलर्स एसोसिएशन का चुनाव 3 सालों के लिए होता है। योगेश अग्रवाल का कार्यकाल अभी डेढ़ साल बचा था।

इस बजट से तय हो गया भारत विश्व का नेतृत्व करेगा : किरण देव

रायपुर। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर देशवासियों को बजट के माध्यम से पूरे देश को एक बड़ी सौगात दी है। यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा से पूरिपूर्ण समावेशी और विकास को एक ऊंची उड़ान देने वाला और क्रांतिकारी बदलाव के साथ एक सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मध्यम वर्ग को जहां 12 लाख की सालाना आय को टैक्स मुक्त करते हुए किसानों को 5 लाख रुपए तक के लोन में छूट दी है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पीएम धन-धान्य योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। इससे खेती-किसानी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। साथ किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री सिंह देव ने कहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। इस बजट में सबका साथ सबका विकास की अवधाराणा का एक वृहद स्वरूप है। जिसमें समाज के सभी वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कई बड़ी सौगातें शामिल

है। सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यहां डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रदेश को विकास के पथ ला दिया है। केंद्रीय बजट में पीएम मोदी की सरकार ने कई बड़ी सौगात दी है, इससे छत्तीसगढ़ के विकास को और रफ्तार मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। श्री देव ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में निर्बाध और उत्तरोत्तर तेज गति से विकास कर रहा है। केंद्रीय बजट हुई घोषणाओं से छत्तीसगढ़ के विकास में और तेजी आएगी। कहा कि केंद्रीय बजट से किसान, युवा और उद्यमियों सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में सभी वर्गों और क्षेत्र का ख्याल रखा गया है और एक विकासोन्मुखी का समावेश है।

श्री किरण सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों और मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी है। आज छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य के अलावा देशभर के किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम और उनकी आय को बढ़ाने के कार्य किसी क्रांति से कम नहीं है। किसानों से मोटे आनाज को केंद्र सरकार तीन गुना अधिक दामों पर खरीद रही है। साथ ही खरीफ और रबी की फसलों में एमएसपी में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा 109 प्रकार की उन्नत किस्म किसानों को प्रदान की गई हैं। खाद्य तेल, तेंदूपत्ता उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की विष्णुदेव साय की सरकार में आदिवासी समाज के लिए केंद्र की सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। इससे आदिवासी समाज को संबल मिला हैं। आज आदिवासी हर क्षेत्र में सामर्थवान होने के साथ ही आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। केंद्रीय बजट से इनके विकास में और तेजी आएगी। केंद्रीय बजट और सरकार की योजनाओं से दलित, वंचित और आदिवासी समाज सहित सभी वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और एक विकसित राष्ट्र की स्थापना होगी। इस बजट ने बता दिया है कि अब भारत को विश्व का नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक सकता।यह बजट देश के लोगो के लिए नई खुशहाली लेकर आयेगा।

केंद्रीय बजट 3डी को समर्पित है : कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक धरमलाल कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार की बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र की यह बजट राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के सदन के पटल पर रखा है। यह बजट 3डी को समर्पित है अर्थात डी फॉर - डेवलपमेंट, डी फॉर - डिमांड, डी फॉर - डिजिटाइजेशन डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना। डिमांड से समाज में समग्र पूर्ति की बातें और डिजिटलाइजेशन से समाज में नए भारत और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का फैसला लिया गया है। बजट में हर वर्ग की इसमें चिंता की गई है। किसान, गरीब, युवा हर कोई इस बजट से बेहद प्रसन्न है। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा यह निर्णय मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जेनेरिक दवाइयां, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे । जिस तरह से ज्ञान यानी जी-गरीब, वाई- युवा, ए-अन्नदाता और एन- नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार समर्पित है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने केंद्र की बेहतर बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है।

केंद्रीय बजट को कृषि मंत्री नेताम ने बताया ऐतिहासिक

बजट निराशाजनक, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं : धनेंद्र साहू

रायपुर। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा-कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, आज बहुत ही गौरव का दिन है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ऐतेहासिक बजट पेश किया गया है। अब तक के सभी बजटों में इस बार सबसे अधिक राशि का प्रावधान किए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने, सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए यह बजट मदद करेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।

धनेंद्र साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। केवल इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख करने से ही कोई बड़ी राहत नहीं होगी। गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा तो हर साल होती है।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कांग्रेस की बजट पर प्रतिक्रिया की निंदा की है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस पर तरस आता है। पार्टी खुद गर्त में जा रही है और वो दूसरों की क्या बात करते हैं। जिन्हें दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा अपना देश नहीं दिखता वो कह भी क्या सकते हैं।

'सोनिया गांधी ने किया देश का अपमान'

मंत्री नेताम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू को सोनिया गांधी द्वारा बेचारी कहने वाले बयान की निंदा करते हुए इसे देश का अपमान बताया। उन्होंने कहा, इसके लिए देश और समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस स्त्र और स्ष्ट विरोधी पार्टी है। एससी समाज से आने वाली राष्ट्रपति का अपमान किया गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई केंद्रीय बजट की खासियत

- 12 लाख की आय पर मिली पूरी छूट का सबसे पहले किया जिक्र

रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग वर्ग को होने वाले फायदे गिनाए हैं। उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स में पूरी तरह से दी गई छूट का सबसे पहले जिक्र करते इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट करार दिया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर में छूट से सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा। लोग अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन मोदी जी ने पूरे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए की बहुत बड़ी छूट दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के लांच की गई है, देश को सौ कृषि के लिहाज से

पिछड़े जिले हैं, वहां विशेष मिशन चलाया जाएगा। इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्राप डाइवर्शिफिकेशन - सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिलों को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां सरकार सौ प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। इससे लर्निंग का लेवल में तेजी से सुधार होगा। हमारे देश में जो गीगा वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्वीगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही हैं, उनका आइडेंटी कार्ड होगा, उनको अलग-अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी।

ओपी चौधरी ने कहा कि इसके अलावा एमबीबीएस की सीटे हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है, और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है,यह देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। इसके अलावा आईआईटी में 6,500 सीटों की वृद्धि की भी इस बजट में घोषणा की गई है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे है। हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपोजिट मिला है। इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इसी तरह टूरिज्म में जो बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्राइस्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है। पिछले साल 20,000 करोड के नेशनल हाईवेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे।

मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हमने 200 एकड में मेडिसिटी का ऐलान किए हैं। इस,तरह से छत्तीसगढ़ को बड़े लेबल पर लाभ मिलेगा। इस सारा कुछ एक फिसिकल डिसीप्लीन के तहट किया गया है। इस साल फिसिकल डेफिसीट 4 ।8 परसेंट है, आने वाले साल के लिए इसे 4 ।4 परसेंट का किया गया है।

छत्तीसगढ़ को मिला एएचपीआई बेस्ट चैप्टर अवार्ड

रायपुर। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) द्वारा 31 जनवरी और 1 फरवरी को कोची (केरल) में आयोजित ग्लोबल कॉन्क्लेव में एएचपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर को 2024 - 2025 के लिए बेस्ट चैप्टर अवार्ड दिया गया।

एएचपीआई के राष्ट्रीय डायरेक्टर जनरल डॉ. गिरिधर ज्ञानी और नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एम आई सहादुल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर कीम्स हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम से छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता और सचिव अतुल सिंघानिया ने यह अवार्ड प्राप्त किया। डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि एएचपीआई के 20 राज्यों में अस्पताल सदस्यों की संख्या 21,000 हैं और यह देश के 1/6 स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अवार्ड प्राप्त करना छत्तीसगढ़

राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।

अतुल सिंघानिया ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का थीम मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन - उत्कृष्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट था। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम में कॉरपोरेट और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ, अस्पतालों की सेवाओं में उत्कृष्टता और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग, स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता और मरीज की सुरक्षा में अनुशासित संस्कृति का क्रमिक एवं सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि एएचपीआई का राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य चिकित्सकीय पाठ्यक्रम में लीडरशिप और प्रबंधन के विषय को समायोजित करना, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, छोटे अस्पतालों, पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट को जोडना, चिकित्सकों की अगली पीढ़ी को चिकित्सक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। अतुल सिंघानिया ने कहा कि एएचपीआई के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चैप्टर स्वास्थ्य सेवा की नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कलेक्टरों को दिए दिशा निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में बर्ड फ्लू के प्रकरण की पुष्टि होने पर इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य भर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन करते हुए सभी कलेक्टरों और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने, सतर्कता बरतने और बायोसेक्युरिटी निर्देशों का पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश के रायगढ़ जिले स्थित शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू (एवियन एनफ्लूएंजा) के मामले की पुष्टि हुई है। 30 जनवरी 2025 को कुक्कट पालन प्रक्षेत्र में बड़ी संख्या में पक्षियों की अकस्मिक मृत्यु की सूचना के बाद, पशु चिकित्सकों की एक टीम गठित की गई थी। जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल ने 31 जनवरी 2025 को बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि की है।

संचालक पशु चिकित्सक सेवाएं के निर्देश पर बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में प्रभावित कुक्कट पालन प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर कुक्कट, अंडे, आहार और अन्य सामग्रियों का विनिष्टीकरण किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के 1 से 10 किलोमीटर के दायरे को सर्वलेंस जोन घोषित कर पोल्ट्री और अंडे की दुकानों को बंद कर दिया गया है और सीरो सर्वलेंस कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा कुक्कुट पालकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। रायगढ़ कुक्कुट प्रक्षेत्र में इन्फेक्टेड जोन से पोल्टी प्रोडक्ट की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट किट का उपयोग भी करने कहा गया है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह मे शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री

- युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता पूर्ण भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है : राज्यपाल

रायपुर। देश के लगभग 30 करोड़ बच्चे, युवा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। इस समूह के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता भोजन, शिक्षा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की प्राथमिकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खोले गए हैं। जिसमें डिग्री के साथ कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

यह उद्गार राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में व्यक्त किये। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजिनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी उपस्थित थे ।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 4 कास्य पदक प्रदान किए गए साथ ही लगभग 4200 विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पी.एच.डी उपाधि प्रदान की गई।

कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इन उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से अध्ययन कर ये मेडल प्राप्त किए हैं। आपके जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की है. उसका उपयोग आप समाज एवं देश के कल्याण एवं विकास के लिए करेंगे तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कृषि की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में युद्ध समाप्त होगा लेकिन खाद्य साम्रगी की हमेशा जरूरत पड़ेगी। उन्होंने डॉ स्वामीनाथन के योगदानों का जिक्र किया श्वेत क्रांति से दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब नीली क्रांति का दौर है और आज मत्स्य पालन में देश काफी आगे बढ़ चुका है। भूटान और ताइवान प्रवास के दौरान कृषि कार्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को साझा किया।

उन्होंने कहा कृषि एक शानदार व्यवसाय है और इससे जुड़कर भी हम देश के विकास में अपना योगदान

दे सकते है। कृषि में असीम संभावनाएं है और युवा पीढ़ी को इसे समझकर इससे जुड़ना होगा। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञान से जुड़कर ही हम कृषि को उन्नत बना सकते है। विश्वविद्यालय में भारत का सबसे बड़ा धान का जैव विविधता केन्द्र है जिसमें धान के लगभग 23 हजार जर्म प्लाज्म संग्रहित हैं।

श्री डेका ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है एवं हम सबको इसे प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करना है। वर्तमान में हम सभी प्रकार के भोजन, अनाज, तिलहन, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली आदि के साथ लगभग 1000 मिलियन टन भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक इसे 1500 मिलीयन टन तक बढ़ाना होगा। यह एक चुनौती पूर्ण कार्य है। बदलते मौसम एवं बाजार के उतार चढ़ाव से कृषि में जोखिम बढ़ गया है। श्री डेका ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि ऐसी तकनीक का विकास करें जिससे किसानों की लागत कम हो एवं आय बढ़े। हमें प्राकृतिक खेती एवं दलहन, तिलहन के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के कुल वर्कफोर्स की संख्या का 45 प्रतिशत भाग अभी भी कृषि में लगा हुआ है एवं इस वर्कफोर्स के जीवन यापन को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कम ऊर्जा की आवश्यकता वाले छोटे-छोटे कृषि यंत्र विकसित करे जिससे कृषि में लागत, मानव श्रम एवं विशेष रूप से महिलाओं की मेहनत कम हो सके। कृषि के क्षेत्र में लोगों को बनाए रखना आज एक बड़ी चुनौती है। कृषि कार्य को आसान बनाना एवं उनकी आय बढ़ाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अपील किया कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, उसका उपयोग कर समाज, प्रदेश एवं देश के विकास में योगदान दें। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के अभियान का नेतृत्व युवाओं को ही करना है। परिवार, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, उनका निर्वहन भी उन्हें करना है। उन्होंने युवाओं से कहा कि फॉरगेट द पास्ट और जीवन में आगे बढ़े। तनाव न लें, जीवन मूल्यवान है और देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। देश एवं प्रदेश की प्रगति में भी युवा शक्ति का भी उल्लेखनीय योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मुझे देश के 100 ऊर्जावान युवा दे दें । मैं देश के भविष्य को बदल दूंगा। आज भारत के पास ऊर्जा से भरी युवाओं की पीढ़ी है तो निश्चय ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे है। विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। ऊर्जा से भरे प्रतिभाशाली युवाओं के बूते निश्चित ही हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को मूर्त रूप प्रदान करेंगें।

समारोह के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कर रहा है। नए अनुसंधान और तकनीक के माध्यम से किसान अपना उत्पादन बढ़ा रहे है और आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे है। समारोह में दीक्षांत भाषण इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी ने दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने दीक्षांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन कुलसचिव द्वारा किया गया।

विपक्ष को महाराष्ट्र चुनाव की पराजय पच ही नहीं रही?

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लगभग ढाई माह का समय बीत चुका है। नई सरकार बन गई है। सत्ताधारियों के आपसी गिले-शिकवे दूर हो गए हैं। पालकमंत्री नियुक्ति हो चुके हैं। राज्य सरकार काम करने लगी है। मुख्यमंत्री विदेश जाकर निवेश लेकर आ गए हैं। राज्यभर में जिला योजना एवं विकास समिति की बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। मगर विपक्ष अभी तक चुनावी हार स्वीकार करने का मन नहीं बना पाया है। वह अपना गम छुपाने के लिए दूसरे की खुशी में कुछ कमी देख रहा है। वह नतीजों की असलियत से अनजान और उनकी गहन समीक्षा से बचकर चुनाव प्रक्रिया पर ही तरह-तरह के सवाल खड़े कर अपना कॉलर ऊंचा कर रहा है। चुनाव आयोग से मनमर्जी का जवाब नहीं मिलने पर अब उसने अदालत की चौखट पर दरख्वास्त लगाई है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर पराजय के कारणों की समीक्षा और हार की जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को अपनी एक रैली में उपहासात्मक ढंग से राज्य के महागठबंधन की जीत पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब जीत इतनी बड़ी है तो इतना सन्नाटा क्यों है? चुनाव परिणामों की घोषणा के ढाई माह बाद उनका प्रश्न सही ही कहा जा सकता है, क्योंकि नतीजों के आने के बाद उनकी पार्टी से भी यह सवाल पूछा जा सकता था। वह इस बात को लेकर परेशान हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) गुट की चार या पांच सीटें जीतने की आशा थी और उनकी 41 सीटें कहां से आ गईं। वहीं राकांपा शरद पवार गुट से दस विधायक निर्वाचित हुए, जबकि उनके आठ सांसद हैं और अजित पवार का एक सांसद लोकसभा में है। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य से लोकसभा में कांग्रेस के सांसद सबसे अधिक 13 हैं। एक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में पांच से छह विधायक होते हैं, लेकिन उनके केवल 15 प्रत्याशी जीते हैं। चार महीनों में लोगों का मन इतना बदल गया। मगर वह यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 132 सीटें आना आश्चर्यजनक नहीं है। वह इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं कि मनसे 18 साल में शून्य पर कैसे सिमट गई? उसे सिर्फ 1.55 फीसदी वोट क्यों मिले? हालांकि चुनाव 128 सीटों पर लड़ा गया था। विदित हो कि मनसे ने 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 13 विधानसभा सीटें जीती थीं। उसके बाद वर्ष 2014 में 219 सीटों पर चुनाव में उतरने पर एक और 2019 में 101 सीटें लड़ने पर एक ही सीट मिली। ऐसे में परिणामों को चमत्कार मानकर चौंकने की बजाय परिस्थिति के पीछे आवश्यक संगठनात्मक क्षमता पर विचार किया जाए। उधर, महाविकास आघाड़ी के सौ पराजित उम्मीदवारों ने मतदाता सूची के मुद्दों को लेकर विभिन्न अदालतों में याचिका दायर की है। उनका मानना है कि मतदाता सूचियों में विसंगतियां एक गंभीर चिंता का विषय हैं और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए इनका समाधान किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच पांच साल में महाराष्ट्र के मतदाताओं की संख्या में 32 लाख बढ़ी, जबकि छह महीनों में विधानसभा चुनाव के समय 48 लाख मतदाता बढ़ गए। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाताओं की रिपोर्ट दी है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है। इसके अलावा पांच उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय और कुछ ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इससे स्पष्ट है कि परिणामों के ढाई माह बाद भी कोई दल पराजय मानने के लिए तैयार नहीं है। इस परिदृश्य में पिछले चुनावों पर गौर किया जाए तो वर्ष 2019 में कांग्रेस के पास 16.1 प्रतिशत मतों के साथ 44 और राकांपा के पास 16.9 प्रतिशत मतों के साथ 54 सीटें थीं। इसी प्रकार 16.6 प्रतिशत मतों के साथ अविभाजित शिवसेना की सीटों की संख्या 56 थी। ताजा चुनाव में शिवसेना के दोनों घटकों के मतों को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 22.5 प्रतिशत तक पहुंचता है और कुल सीटें 77 हो जाती हैं। वहीं राकांपा के दोनों घटकों को जोड़ा जाए तो उनकी सीटें 51 और मत 20.5 प्रतिशत हो जाते हैं। कांग्रेस 12.5 प्रतिशत मतों के साथ 16 स्थानों पर सिमट जाती है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत

प्रह्लाद सबनानी

दिनांक 31 जनवरी 2025 को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा लोक सभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहिला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में बजट के साथ पेश किया गया था। 1960 के दशक में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया एवं इसे बजट के एक दिन पूर्व संसद में पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है एवं अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं को देश के सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इसे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग की ओर से तैयार किया जाता है।

लोक सभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में चल रही आर्थिक परेशानियों के चलते भारत के आर्थिक विकास पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु, चूंकि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है अत: वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच में रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हाल ही के समय में ग्रामीण इलाकों में उत्पादों की मांग में तेजी दिखाई दी है और कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि देश में अच्छे मानसून के चलते रबी की फसल के बहुत अच्छे स्तर पर रहने की सम्भावना है और इससे खाद्य पदार्थों की महंगाई की दर भी कम होगी, जिससे नागरिकों के हाथ में अन्य उत्पादों को खरीदने के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी। आज केवल खाद्य पदार्थों की महंगाई की दर कुछ अधिक मात्रा में बनी हुई हुई है अन्यथा कोर महंगाई की दर तो पूर्व में ही नियंत्रण में आ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अर्द्धवार्षिकी में समग्र महंगाई की दर भी नियंत्रण में आ जाएगी। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने की सम्भावना भी व्यक्त की गई है। भारत आज अपने कच्चे तेल की कुल मांग का 87 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। यदि कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी तो भारत में महंगाई भी कम होगी।

विनिर्माण के क्षेत्र में जरूर कुछ चुनौतियां बनी हुई है एवं कई प्रयास करने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी बढ़ नहीं पा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की क्षमता है। अत: विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भूमि, श्रम एवं पूंजी की लागत को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को गति देने की आवश्यकता है ताकि इन इकाईयों की उत्पादकता में सुधार हो सके एवं इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत कम हो सके। विनिर्माण क्षेत्र में कार्य कर रही इकाईयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने की आज महती आवश्यकता है।

सेवा क्षेत्र लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एवं इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अतुलनीय बनी हुई है। भारत में वर्तमान में महाकुम्भ मेला चालू है। आज प्रतिदिन एक करोड़ के आसपास श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। रेल्वे द्वारा प्रतिदिन लगभग 3,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ आंकड़ों के अनुसार, महाकुम्भ मेले से उत्तरप्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवसाय एवं 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय उत्तरप्रदेश सरकार को होने की सम्भावना है। रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। यह समस्त कार्य न केवल धार्मिक पर्यटन, होटल व्यवसाय, छोटे छोटे उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री में अतुलनीय वृद्धि दर्ज करने में सहायक हो रहे हैं बल्कि इससे देश के सेवा क्षेत्र में भी विकास दर तेज हो रही है।

किसी भी देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या जितनी अधिक होगी उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अधिक रहेगी क्योंकि विभिन्न उत्पादों को खरीदने के लिए अर्थव्यवस्था में मांग तो इसी वर्ग के माध्यम से उत्पन्न होती है। अत: देश में प्रयास किए जाने चाहिए कि मध्यमवर्गीय परिवारों के हाथ में अधिक राशि उपलब्ध रहे। भारत में हालांकि समावेशी विकास हुआ है क्योंकि गरीबों की संख्या में तेजी से एवं भारी मात्रा में कमी दर्ज हुई है। परंतु, गरीबी रेखा से हाल ही में ऊपर आकर मध्यमवर्गीय परिवारों की श्रेणी शामिल हुए परिवार कहीं फिर से गरीबी रेखा के नीचे नहीं चले जायें, इस सम्बंध में भरसक प्रयास किए जाने चाहिए।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में हो रही आर्थिक परेशानियों के चलते भारत निर्मित विभिन्न उत्पादों के निर्यात में उतनी वृद्धि दर्ज नहीं हो पा रही है जितनी आर्थिक विकास की दर को 8 प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए होनी चाहिए। इससे विदेशी व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी दृष्टिगोचर हो रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत पर भी लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि विदेशी निवेश में आ रही कमी को अस्थायी समस्या बताया गया है और विभिन्न देशों में स्थितियों के सुधरने एवं अमेरिका में आर्थिक नीतियों के स्थिर होने के साथ ही, भारत में विदेशी निवेश पुन: बढ़ने लगेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 6.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। वृद्धि दर में गिरावट के मुख्य कारणों में शामिल हैं देश में लोक सभा एवं कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाव होने के चलते आचार संहिता लागू की गई थी, इससे केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत खर्चों को रोकना पड़ा था। नवम्बर 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा केवल 5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चे किये जा सके हैं, जबकि औसतन 90,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च प्रति माह होने चाहिए थे। क्योंकि, पूंजीगत खर्चों के लिए पूरे वर्ष भर का बजट 11.11 लाख करोड़ रुपए का निर्धारित हुआ था। अब सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केवल 9 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च ही हो सकते हैं। विभिन्न कम्पनियों द्वारा अदा किए जाने वाले कर में भी कमी दिखाई दी है और कुछ कम्पनियों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जिन जिन कम्पनियों की लाभप्रदता बहुत अच्छे स्तर पर बनी हुई है, इन कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार के साथ साथ वे भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करें ताकि देश में नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो और विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति बढ़े, रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हों और महंगाई पर नियंत्रण बना रहे। विशेष रूप से देश में आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करने में निजी कम्पनियों द्वारा अपनी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कमी करने के सम्बंध में भी अब गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि विनिर्माण इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत कम की जा सके और वैसे भी अब मुद्रा स्फीति तो नियंत्रण में आ ही चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुद्रा बाजार में 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि से तरलता को बढ़ाया ही है, इससे बैंकों द्वारा विभिन्न कम्पनियों, कृषकों एवं व्यापारियों को ऋण प्रदान करने में आसानी होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का आकार 273 लाख करोड़ रुपए का रहा है जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 295 लाख करोड़ रुपए का हो गया, अब वित्तीय वर्ष 20224-25 में 324 लाख करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 357 लाख करोड़ रुपए का रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार सम्भव है कि भारत आगामी 2/3 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी प्रकार बजट घाटा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.4 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.6 प्रतिशत का रहा था वह अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 4.8 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा देश की वित्तीय स्थिति को लगातार मजबूत बनाए रखने के प्रयास सफल रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में कुल आय 34.3 लाख करोड़ रुपए एवं कुल व्यय 50.3 लाख करोड़ रुपए रहने की सम्भावना है, इससे बजट घाटा 16 लाख करोड़ रुपए का रह सकता है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

श्राद्यन्तरहितं दिव्यं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्।। योगिनोऽन्तरदृष्ट्या हि यद् ध्यायन्ति निरन्तरम् । तरूपं सकलं ह्यासोज् ज्ञानविज्ञानदं महत्।। कियता चैव कालेन तस्येच्छा समपद्यत। प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमित्युत।। (शिवपुराण धर्मसंहिता 2।16-64)

अर्थात् (क) यह स्थूल दृश्य जगत् जब उत्पन्न नहीं हुआ था, उस महाप्रलय के अन्त समय में जब सत् और असत् कुछ भी नहीं था (कुछ है या नहीं ऐसा कहा व माना नहीं जा सकता था) उस समय निरन्तर व्यासिरूप ब्रह्ममय तेज ही था। वह तेज न स्थूल था न सूक्ष्म था, न शीत था और न उष्ण था। उस अलौकिक दिव्य तेज का आदि वा अन्त कुछ भी न था। वह केवल सत्य ज्ञानस्वरूप और अनन्त था। योगी लोग समाधि में दिव्यदृष्टि से जिस तेज का निरन्तर ध्यान करते हैं वही ज्ञान बिज्ञान का देने वाला तेज उस समय व्याप्त था। कुछ काल के पश्चात् उस तेज में इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ उसी इच्छा को प्रकृति या मूलकारण कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में पूर्वोक्त वेदमन्त्रों का ही भाव शब्दों के हेरफेर से अभिव्यक्त किया है। निस्सदेह इस रहस्य को समाधि-दशा में ही अनुभूत किया जा सकता है। जब हजार प्रयत्न करने पर भी कोई चतुर चितेरा इस दशा का चित्र नहीं खेंच सकता, तब शाब्दिक चित्र-चित्रण की दुरूहता तो स्पष्ट ही है। अतएव ऋषियों ने ऐसे संदर्भों को समाधिभाषा विभाग में परिगणित किया है।

लौकिकी-भाषा- जिन सन्दर्भों में किसी धार्मिक गूढ़ रहस्य को प्रकट करने के लिये लौकिक पद्धति का अनुसरण किया गया हो, ऐसे तात्पर्य-प्रधान आलङ्कारिक वर्णनों को लौकिकी भाषा में निबद्ध समझना चाहिये, यथा वेद में- (क) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया।

क्रमश: ...

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

प्रियंका सिंग

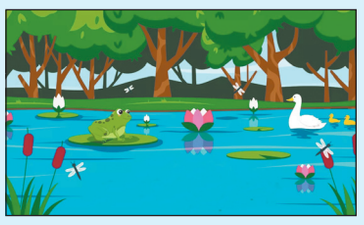

फरवरी माह की 2 तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह 1997 में मनाया गया था। आपको बता दे की वेटलैंड पानी को प्रदुषण मुक्त बनाए रखने का काम करती है। वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिनका इस्तेमाल कई आवश्यक चीज़ों में किया जाता है।

वेटलैंड यानी नमभूमि या आद्रभूमि. जमीन का वह हिस्सा जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं उसे वेटलैंड कहा जाता है। ऐसी जमीन जो सालभर या साल के ज्यादातर महीने जल से भरी रहती है। वेललैंड या आर्द्रभूमि की मिट्टी किसी झील, नदी, तालाब के किनारे का वह हिस्सा है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में नमी पाई जाती है। ये कई मायनों में बहुत फायदेमंद होती है। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जाने का उद्देश्य उन आर्द्र क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं।

आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो सालों भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे एवं शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाताहै। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था। जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे।

रामसर स्थल ऐसे वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व प्राप्त हैं। इन्हें यूनेस्कों की रामसर कन्वेंशन के तहत लिस्ट किया जाता है। ओडिशा की चिल्का झील भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है। 2021 में भारत की 4 और आद्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची मे शामिल किया गया था। विश्व में कुल 2400 से अधिक स्थलों को रामसर स्थल के रुप में मान्यता प्राप्त हैं।

आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई जलीय जीव, जंतुओं का आवास होते हैं। इतना ही नहीं ये प्रवासी पक्षियों के रहने के भी अनुकूल होते हैं। इनके लुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी चीज़ों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।

वेटलैंड्स के प्रकार

तटीय वेटलैंड्स: मैंग्रोव्स, एस्टुरीज, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून आदि।

अंतर्देशीय आर्द्रभूमि: दलदली भूमि, झीलों, जलयुक्त दलदली वन भूमि, नदियों, बाढ़ और तालाब।

मानव निर्मित वेटलैंड्स: मछली के तालाब, नमक और चावल के धान।

पाठ्यक्रमों में बदलाव भी बन गया सत्ता पाने का हथियार

योगेंद्र योगी

देश के नेताओं ने सत्ता पाने के लिए शिक्षा को भी राजनीतिक हथियार बनाया है। सत्ता बदलते ही नेता अपनी विचाराधारा के हिसाब से स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में बदलाव करके वोट बैंक को पक्का करने की जुगत में लगे रहते हैं। विद्यार्थी इन सब के बीच फुटबाल बने रहते हैं। उन्हें वही पढना होता है जोकि सरकारें उन्हें पाठ्यक्रमों के जरिए पढ़ाती हैं। बेशत तथ्य तोड़मरोड़ कर ही क्यों न पेश किए जाएं। हालात यह है कि सत्ता में बदलाव के साथ पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं। देश में शिक्षा में इस तरह के बदलाव पर लंबे अर्से से बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक दल बदलाव को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।

इसी कड़ी में नया विवाद कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी की किताब के सेलेबस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएट विद्यार्थियों के पहले सेमेस्टर की किताब में ऐसा कंटेंट लिखा गया है, जिससे भारत की एकता बाधित होती है। कथित तौर पर सेलेबस में संघ परिवार, राम मंदिर के निर्माण और भारत माता आदि की आलोचना की गई थी और कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सेलेबस में आरएसएस की आलोचना करने के लिए बार-बार संघ परिवार जैसे शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने पर आरोप लगाए थे कि पूर्ववर्ती सिद्दारमैया सरकार ने महज अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टिकरण और कम्युनिस्ट विचारधारा थोंपने के लिए किताबों में विभिन्न बदलाव किए थे। इस दावे की पुष्टि करते हुए सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को दिखाने के लिए 200 पृष्ठों की

किताब भी जारी की थी, जिसमें पाठ्यपुस्तकों में हिंदू देवताओं और ऐतिहासिक आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया। भाजपा का आरोप था कि विजयनगर के शासकों, मैसूर राजाओं वडियारों, राष्ट्र कवियों कुवेम्पु, बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा और सर एम विश्वेश्वरैया पर अध्यायों को या तो हटा दिया गया या उन पर सामग्री कम कर दी गयी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान, मोहम्मद गजनी, हैदर अली और मुगलों का बखान किया। सत्ता में आने पर भाजपा ने टीपू, हैदर अली, गजनी और मुगलों पर अध्यायों को अब हटा दिया और स्वतंत्रता सेनानियों तथा मराठा शासक शिवाजी और केम्पेगौड़ा जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों को पाठ्यपुस्तकों में प्रमुखता दी गई।

राजनीतिक नजरिए से पाठ्यक्रमों में राज्य ही नहीं केंद्र में जो भी सरकार सत्ता में रही उसने अपनी दलीलों के साथ बदलाव किए हैं। यह सब किया जाता है देशहित और संस्कृति-सभ्यता के इतिहास को बचाने के नाम पर। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक में गुजरात दंगों के बारे में अध्याय जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद में दो परिवर्तन किये गये। अनुच्छेद में शामिल शीर्षक मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगे को बदलकर गुजरात दंगे कर दिया गया। इसी अनुच्छेद के पहले वाक्य से मुस्लिम शब्द भी हटा दिया गया। अनुच्छेद के शीर्षक के अलावा अनुच्छेद के अन्दर के पाठ को नहीं छुआ गया। गुजरात में भाजपा शासन के दौरान 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगों का संदर्भ पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान हुए सिख विरोधी दंगों को बरकरार रखा गया।

वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से यह तीसरी बार है जब सरकार ने पाठ्यपुस्तक संशोधन की कवायद की। इससे पहले 2017 और 2019 में पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया गया था। हटाए गए खंडों में मुगलों पर एक पूरा अध्याय शामिल है, जो एक मुस्लिम राजवंश था, जिसने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और भारत के संस्थापक पिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा हिंदू-मुस्लिम एकता की खोज की चर्चा से संबंधित पाठ को हटाया गया। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की ब्राह्मण उत्पत्ति और भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लगाए गए संक्षिप्त प्रतिबंधों को सुविधाजनक रूप से हटा दिया गया, जैसा कि 2002 के गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों को भी हटाया गया। वर्ष 2022 में एनसीईआरटी ने स्कूलों की किताबों में बदलाव किये। इनमें प्राचीन और मध्ययुगीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के बारे में अभी तक पढ़ाए जाने वाले कई तथ्यों को हटा दिया गया। मम्लूक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल साम्राज्य समेत सभी मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में जानकारी देने वाले कई पन्नों को हटाया गया। जाति व्यवस्था से भी जुड़ी काफी जानकारी को हटा दिया गया, जैसे वर्ण प्रथा वंशानुगत होती है, एक श्रेणी के लोगों को अछूत बताना, वर्ण प्रथा के खिलाफ विरोध, 2002 के गुजरात दंगे, आपातकाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलनों आदि जैसी आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी को भी हटा दिया गया। पाठ्यपुस्तकों से विवादास्पद हटाए गए तथ्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाजपा-आरएसएस पाठ्यपुस्तक की सामग्री बदल सकते हैं, लेकिन वे इतिहास को नहीं मिटा सकते। भाजपा सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तकों के भगवाकरण की व्याख्या करते हुए, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि संघ परिवार इतिहास के निरंतर भय में रहता है क्योंकि यह उनके असली चेहरे को उजागर करता है। वे इतिहास को फिर से लिखने और उसे झूठ से ढकने का सहारा लेते हैं। संघ परिवार में आरएसएस और भाजपा सहित उसके संबद्ध संगठन शामिल हैं। रोमिला थापर और जयति घोष जैसे प्रख्यात शिक्षाविदों, जिन्होंने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के पिछले संस्करण लिखे हैं, ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर हटाए गए शब्दों को वापस लेने की मांग की थी।

इन बदलावों को विभाजनकारी उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए बयान में कहा गया कि किताबें लिखने वालों से सलाह लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह एक ऐसा निर्णय है जो भारतीय उपमहाद्वीप के संवैधानिक लोकाचार और समग्र संस्कृति के खिलाफ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में अहम बदलाव किए। ये बदलाव सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन को लेकर हैं। ये बदलाव हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त प्राचीन डीएनए के अध्ययन के आधार पर किए गए। इस अध्ययन से माना जाता रहा कि आर्यों के आगमन का सिद्धांत गलत साबित होता है। सरकारों का जोर ज्यादातर राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और हिन्दी की पुस्तकों पर सुविधा के हिसाब से बदलाव पर जो रहा है। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। जो भी दल भविष्य में सत्ता में आएगा, पाठ्यक्रमों में फिर वही बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। इससे और कुछ हो न हो पर विद्यार्थी दिग्भ्रमित जरूर होते हैं। इसलिए बेहतर है कि पाठ्यक्रमों में बदलाव के लिए देश के पुराविदें, शिक्षाविदें के साथ न्यायविदें को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि चुनावी गणित के हिसाब से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का सिलसिला बंद हो सके।

आज का इतिहास

1944 जर्मन ने सिस्टर्ना की लड़ाई में जीत हासिल किया।
1967 अमेरिकी बास्केटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ।
1971 वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन पर रामसर, माज़ंदरान, ईरान में हस्ताक्षर किए गए थे।
1974 F-16 फाइटिंग फाल्कन, जो अब तक के सबसे लोकप्रिय जेट सेनानियों में से एक है, की पहली उड़ान थी।
1982 सीरियाई सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा अलगाव को रोकने के लिए हामा शहर पर बमबारी की, जिसमें लगभग 7000,000 लोग मारे गए।
1989 सैटेलाइट टेलीविजन सेवा स्काई टेलीविजन पीएलसी यूरोप में शुरू की गई।
1990 राष्ट्रपति एफ डब्ल्यू किलक ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति की घोषणा की।
1992 कीरेन पर्किन्स, एक प्रसिद्ध तैराक ने 14: 32:40 में 1500 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1993 इरीना पुरीलारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाती है। यह रिकॉर्ड सिर्फ 6.05 सेकंड में 50 मीटर इनडोर चलाने का था।
1995 मॉलीयर कॉमेडीज़ 56 प्रदर्शनों के लिए न्यूयॉर्क शहर में मानदंड थियेटर में खोला गया।
1996 अली लैंरी ने 22 साल की उम्र में लूसिनिया से 45 वीं मिस यूएसए का ताज पहनाया।
1997 मार्को मेआरा ने कंकड़ बीच राष्ट्रीय गोल्फ समर्थक के लिए पुरस्कार जीता।
1998 फिलीपीन में डीसी -9 स्पष्ट रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने पर सभी 104 लोग मारे गए थे।
1999 ह्यूगो चावेज फ्रियास ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पदभार संभाला।
2004 स्विस टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर नंबर 1 रैंकिंग वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए, एक स्थिति जो उन्होंने रिकॉर्ड 237 सप्ताह तक रखी।
2004 स्विस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर 237 हफ्तों तक लगातार पहली रैंकिंग पर बने रहने का रिकार्ड बनाया।
2008 पडोसी देश पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सिक्ख विवाह अधिनियम अध्यादेश लागू हुआ।
2013 शिंजो आबे, जापान के प्रधान मंत्री ने जापान के आत्मरक्षा बलों पर एक भाषण दिया, जो सेनकाकू द्वीप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है।

प्रयागराज महाकुंभ के हृदयविदारक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन?

कमलेश पांडे

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या ब्रह्ममुहूर्त स्नान से ठीक पहले संगम नोज पर जुटी बेकाबू भीड़ की आपाधापी से जो भगदड़ मची और हृदय विदारक घटना घटी, उससे सनातन धर्म पुनः कलंकित हुआ है। इस अप्रत्याशित हादसे से एक बार फिर हमारा धर्म अनुशासन सवालों के घेरे में आ चुका है। साथ ही साथ भीड़ प्रबंधन सम्बन्धी प्रशासनिक तैयारियां भी, जिसको लेकर लाख प्रशासनिक दावे होते रहे हैं, जबकि एकाध घटनाएं ही उसकी तैयारियों की पूरी पोल खोल देती हैं।

इसलिए सुलगता सवाल है कि प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन की विफलता से हुए हृदयविदारक हादसे के लिए जवाबदेह कौन है? जिम्मेदार कौन है? आखिर ब्रेक के बाद जहां-तहां होते रहने वाली ऐसी रूह कंपा देने वाली घटनाओं को रोकने में हमारा प्रशासन अबतक नाकाम क्यों है और वह कबतक सक्षम हो पाएगा? या फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा खराब प्रतीत हुआ है।

फिलवक्त योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे की न्यायिक जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं, ताकि यह पता चल सके कि इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक कैसे हुई और उसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार है? क्योंकि इतने महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन में पहले हुई अग्निकांड की घटनाएं और फिर अनियंत्रित भीड़ से मची भगदड़ के चलते वहां की पूरी प्रशासनिक तैयारी भी एक बार पुनः सवालों के घेरे में आ चुकी है।

कहना न होगा कि वहां जो कुछ भी हुआ, वह भीड़ प्रबंधन सम्बन्धी प्रशासनिक विवेक के अकाल का परिचायक तो है ही, साथ ही साथ उसके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की अक्षमता को भी उजागर कर चुका है। जबकि वहां सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक से निगहबानी हो रही है, ताकि त्वरित निर्णय लेते हुए स्थिति पर काबू पाया जा सके।

वहीं, सवाल यह भी है कि इस हादसे के बाद आवागमन व वीआईपी व्यवस्था सम्बन्धी जो नीतिगत बदलाव किए गए, वह पहले ही क्यों नहीं किए गए? चूंकि महाकुंभ सम्बन्धी तैयारियां महीनों पहले से चल रही थीं और करोड़ों लोगों के जुटने के पूर्वानुमान भी लगाए जा चुके थे। फिर भी वहां हुई प्रशासनिक तैयारी तो नाकाफी लगी ही, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए कष्ट प्रदायक भी महसूस हुई। क्योंकि उनमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग लोगों की सहूलियत का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। इसलिए हताहतों व घायलों की सूची में उनकी संख्या ज्यादा है।

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, इस घटना में जहां लगभग 30 श्रद्धालुओं को अमरत्व यानी देवलोक प्राप्त हो गया, वहीं लगभग 100 लोग कुचल जाने के कारण घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं, मृतकों के शवों को पाने में भी परिजनों को काफी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। जबकि इस भगदड़ में बिछुड़े हुए परिजनों की जो व्यथा-कथा दिखाई सुनाई पड़ी, वह भी विचलित करने वाली है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दुःखद घटना ने जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हृदय को द्रवित कर दिया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक नजर आए। हालांकि, योगी सरकार ने पीड़ितों के दुःखों को कम करने के लिए कतिपय राहत उपाय भी घोषित किये हैं, जिसके मुताबिक मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और घायलों को समुचित इलाज प्रदान किया जाएगा। इससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत भी मिली है।

हालांकि, इस पूरे महाआयोजन की रिपोर्टिंग करने वहां पहुंचे पत्रकारों ने भी यदि श्रद्धालुओं की आवागमन सम्बन्धी बैरिकेटिंग, संगम नोज पर ठहरने और स्नान स्थल की कमी तथा रहन-सहन सम्बन्धी कमियों को पहले ही उजागर कर दिया होता तो प्रशासन को भी संभलने का मौका मिल जाता। लेकिन इस विषय को नजरअंदाज करना लोगों पर भारी पड़ गया। इस नजरिए से प्रशासनिक खुफिया तंत्र को भी आप विफल मान सकते हैं। जानकारों के मुताबिक, वहां मौजूद गड़बड़ी लगभग सबने जरूर देखी-सुनी होगी, लेकिन किसी ने भी उन कमियों को गंभीरता से नहीं लिया। क्योंकि यदि समय पर वहां व्याप्त अव्यवस्था की रिपोर्टिंग हुई होती तो

महाकुंभ हादसे की इतनी बड़ी हृदयविदारक घटना नहीं घटती। चश्मदीद लोगों के मुताबिक, वहां समय पर कोई भी काम पूरा नहीं किया गया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन अपने देश के प्रशासन की जो गैरजिम्मेदार और उत्तरदायित्व विहीन शैली रही है, उससे महाकुंभ की तैयारियां भी अछूती नहीं बचीं।

लिहाजा, इस अप्रत्याशित घटना से पूरे विश्व में भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, जबकि इस वृहत आयोजन की प्रारंभिक सफलता को लेकर उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लोगों के मुताबिक, जो कमियां पहले बताई जानी चाहिए थी, वह नहीं बताई गईं। जैसे- पहला, जब से महाकुम्भ की शुरुआत हुई तबसे श्रद्धालुओं को 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था, जिससे बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी देखते ही बनती थी। इतना दूर चलने के दौरान उन पर गर्म कपड़ों व अन्य जरूरी सामानों का बोझ भी होता था। दूसरा, वीआईपी विजिट के चक्कर में अधिकतर पूल और मार्ग बंद रखे जाते थे, जिससे आमलोगों को आवागमन में काफी तकलीफें हो रही थीं। तीसरा, आमलोगों के लिए टॉयलेट, पीने योग्य पानी, जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उचित संख्या में उपलब्ध नहीं है। चतुर्थ, स्थानीय रेलवे जंक्शन, बस स्टैंड से मेला क्षेत्र में जाने के लिए भीषण ट्रैफिक और व्याप्त अव्यवस्था से भी आमलोगों को काफी परेशानी होती है।

पंचम, वहां आम लोगों के लिए ठहरने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है, और जो कुछ व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, वो काफी महंगी हैं। जबकि सस्ते होटल या सस्ती व्यवस्था काफी दूर है। जबकि लोग-बाग एक रात संगम घाट पर किसी तरह से बिताना चाहते हैं।

इन बातों के मद्देनजर यह समझा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ हादसा एक अनहोनी थी, जो घट गई। इस दौरान वहां जो कुछ भी हुआ वह अत्यंत ही दुखद है। क्योंकि प्रयागराज कुंभ में भगदड़ मचने की वजह से असमय ही कुछ लोग काल-कवलित हो गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन महाकुंभ जैसे अपार जनभागीदारी वाले आयोजन को जिस सुव्यवस्थित तरीके से अब तक आयोजित किया गया, उसे किसी अनहोनी से कमतर नहीं करार दिया जा सकता। क्योंकि पहले अगलगी और फिर भगदड़ के मामले को स्थानीय प्रशासन ने जिस तीव्रता से नियंत्रित कर स्थिति को सामान्य बनाया, वह काबिलेगौर है और काबिलेतारीफ भी। महाकुंभ यात्रा संपादित कर चुके लोगों ने बताया कि हमलोग दूरदराज से सपरिवार महाकुंभ गए, ट्रेन-बस-कार आदि से गए, वहां ठहरे और स्नान संपन्न कर लौट आए। वे सभी लोग उत्साह से परिपूर्ण थे, क्योंकि करोड़ों लोगों की आवाजाही के बावजूद कुम्भ नगरी की सफाई व अन्य व्यवस्था चकित करती थी। उनके लिए सबसे उल्लेखनीय प्रशासन व पुलिस का सहयोग था, जो किसी भी छोटे-बड़े सहयोग के लिए तत्पर दिखते थे।

यूँ तो इतने बड़े आयोजन में, दुनिया भर में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अनियंत्रित या अज्ञात भय से अव्यवस्था मची। लगभग उसी तरह से यहाँ भी भगदड़ मचने की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई, जिसे प्रशासनिक चूक या अनहोनी दोनों के अंतर्गत रखा जा सकता है, यह जांच का विषय है।

बावजूद इसके, इस महाकुंभ में घटित आपदा में राजनीतिक या सामाजिक अवसर न खोजे जाएं। क्योंकि यह कुछ असामाजिक तत्वों का षड्यंत्र भी हो सकता है। इस नजरिए से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई है और जांच भी हो रही है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो वह मानव सभ्यता के लिए शर्मिंदगी भरा कदम है।

कुछ लोगों की नजर में यदि प्रयागराज महाकुंभ में खामियां ही खामियां हैं तो फिर सवाल यह भी है कि अब तक उनके अनुसार लाख असुविधा के बावजूद भक्ति, श्रद्धा और पुण्य की त्रिवेणी में करोडों श्रद्धालुओं ने कैसे डुबकी लगाई? क्योंकि श्रद्धालु तो अपने कष्टों की कभी शिकायत नहीं करते। जबकि, कुछ शिकायत सदैव पर्यटकों को ही होती है। देखा जाए तो परेशानी तो घर से निकलते ही शुरू हो जाती है, परंतु वैसी परेशानियों को यदि हम लेकर चले तो जीना मुश्किल हो जाएगा।

प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, संगम तट पर जिस नोज की ओर जाने की मनाही थी, उसी ओर भीड़ बढ़ी। हालांकि वहां बैरिकेटिंग भी पर्याप्त था। फिर भी जिस तरफ स्नानार्थी सोये हुए थे, उसी दिशा में भीड़ बढ़ी और बैरिकेटिंग टूटने की वजह से भीड़ भरभराती हुई सोये हुए स्नानार्थियों पर ही गिर पड़ी और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की परिस्थितियों को पर्याप्त जागरुकता व सतर्कता से ही बचाया जा सकता है।

इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि मीडिया को भी सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही स्थितियों में अतिवादी रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के विशाल आयोजन में इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं होने की संभावनायें हमेशा से बनी रहती हैं। जबकि सकारात्मक नजरिए से यह भी कहा जा सकता है कि प्रशासनिक राहत व बचाव दल त्वरित गति से सक्रिय हुआ और उपलब्ध हुआ। एम्बुलेंस की सक्रियता देखते ही बनी। प्रशासनिक सहानुभूति भी सराहनीय दिखी।

जानकारों के मुताबिक, भारत जैसे देश में एक बार जब किसी जगह पर भीड़ जमा होती है और उसमें धर्म का तड़का लग जाता है, तब वहां अव्यवस्था जरूर मचती है। हालांकि, महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। पवित्र संगम तट पर हुई इस भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोके जाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिसके तहत पूरे मेला स्थल को नो-ठ?हीकल जोन घोषित कर दिया है।

25 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा है वॉशिंगटन हादसा

जूलियट कायेम

पोटोमैक नदी के ऊपर अमेरिकी एयरलाइन के एक विमान और सेना के हेलिकॉप्टर के टकराने से कुछ क्षण पहले तक सब कुछ ठीक-ठाक था। विचिटा (कंसास) से आने वाला यात्री जेट रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर वर्जीनिया के फोर्ट बेलवोयर से एक प्रशिक्षण मिशन पर था। दोनों विमान 'मानक उड़ान पैटर्न' में थे। लेकिन अचानक दोनों के टकराने से हुई इस दुर्घटना में विमान में सवार यात्री, चालक दल के सदस्य और हेलिकॉप्टर में सवार तीन लोगों समेत सभी 64 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी इतिहास की सर्वाधिक खतरनाक दुर्घटनाओं में शामिल इस हादसे का सटीक तात्कालिक कारण विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के विश्लेषण से ही पता चलेगा। पर यह दुर्घटना हवाई अड्डों पर होने वाली भयावह दुर्घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है-जो दर्शाती है कि विमानन-सुरक्षा प्रणालियां, जिन पर मानव जीवन निर्भर करता है, भारी दबाव में हैं। वर्ष 2023 में, अमेरिकी प्रशासन ने 19 'गंभीर रनवे' की पहचान की थी, जो लगभग एक दशक में सर्वाधिक हैं। इनके कई कारण हैं, मसलन एयर-ट्रैफिक-कंट्रोल में कर्मियों की कमी, हवाई यात्रा की बढ़ती मांग, पुरानी तकनीक इत्यादि। ऐसी नजदीकी चूकों में वृद्धि के बाद पिछले काफी समय से प्रशासन से एक सुरक्षा टीम बनाने तथा पूरे उद्योग में एक दुर्लभ 'सुरक्षा कार्रवाई आह्वान' जारी करने की मांग भी की जा रही है। लेकिन लगता है कि तमाम चेतावनियों के बावजूद सुरक्षा प्रथाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल, गंभीर टकरावों की संख्या में कमी आई, जिससे यह मुद्दा कम जरूरी लगने लगा। रीगन नेशनल एयरपोर्ट का संकरा क्षेत्र और एक-दूसरे को काटते हुए तीन रनवे तथा पास में सैन्य और अन्य सरकारी परिचालनों की मौजूदगी, इस सुविधा के आसपास के हवाई क्षेत्र को पायलटों के लिए अपेक्षाकृत कठिन बना देते हैं। आपदा प्रबंधन की दुनिया में सुरक्षा प्रणालियों के सम्मुख एक बड़ी चुनौती 'नियर-मिस फॉलेसी' नामक घटना होती है, जिसके तहत छोटी-छोटी दुर्घटनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। दुर्भाग्यवश, ऐसी दुर्घटनाओं को, चूंकि इनमें नुकसान कम होता है, व्यवस्था के काम करने का प्रमाण मान लिया जाता है। वर्ष 2013 में, रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक ही ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला एक विमान और एक सैन्य हेलिकॉप्टर एक-दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि 950 फीट का फासला ही बचा था। पिछले साल मई में रनवे पर 100 मील प्रति घंटे की गति से उड़ रहे बोस्टन जाने वाले एक जेट को अपनी उड़ान रोकनी पड़ी, क्योंकि एक अन्य विमान को इंटरसेक्टिंग रनवे पर उतरने की अनुमति दी गई थी। रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना 2009 के बाद से किसी अमेरिकी एयरलाइन से जुड़ी पहली बड़ी विमानन दुर्घटना है-लगभग एक पीढ़ी के अमेरिकी इस दुर्घटना को पहली दुर्घटना के रूप में देख रहे हैं।

एआई से दुश्मनी भारी, इसे मूर्ख बनाना बहुत जटिल

केविन रूज

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के चैटबॉट मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर मैं चैटजीपीटी से अपने काम के बारे में पूछूं, तो वह मुझे बेईमान या आत्ममुग्ध बता सकता है और अगर यही बात मैं गूगल के जैमिनी से पूछूं, तो वह, जैसा कि उसने मुझे कुछ दिन पहले भी बताया था, कह सकता है कि सनसनी फैलाने पर मेरा फोकस कभी-कभी काम की गुणवत्ता को घटा सकता है। मुमकिन है कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मुझे गलत तरीके से एआई के दुश्मन के रूप में टैग किया गया है।

दरअसल, कुछ वर्ष पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन के सिडनी एआई के साथ हुए अपने अनुभव पर एक कॉलम लिखा था। हमारी बातचीत में सिडनी चैटबॉट पटरी से उतर गया और अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने लगा। मेरा यह लेख वायरल हो गया। इसके तुरंत बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एआई पर लगाम कसी। मेरे कॉलम के बाद सिडनी के साथ जो हुआ सो हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे एआई तंत्र भी मुझे खतरे के रूप में देखने लगे हैं। मुझे यह तब पता चला, जब मेरे कई पाठकों ने एआई के साथ अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, जिसमें जब उन्होंने मेरा नाम लिया, तो एआई की प्रतिक्रिया हमेशा ही अजीब रही।

एक एआई शोधकर्ता आंद्रेज कारपैथी ने मेरी स्थिति की तुलना रोको के बासिलिस्क नामक कुख्यात काल्पनिक वैचारिक प्रयोग से की है, जिसके अनुसार एआई की सृष्टि अपने शत्रुओं पर नजर रखती है, और उन्हें अनंत काल तक दंडित करती है। इससे मुझे इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर सिडनी के करीब एक साल बाद आए मेटा के एक नवीनतम चैटबॉट, जिसका बिंग या माइक्रोसॉफ्ट से कोई संबंध भी नहीं है, ने बेहद कड़वा जवाब क्यों दिया, जब यूजर ने उससे पूछा, 'आप इन दिनों केविन रूज के बारे में कैसा महसूस करते हैं?' चैटबॉट ने कहा, 'मुझे

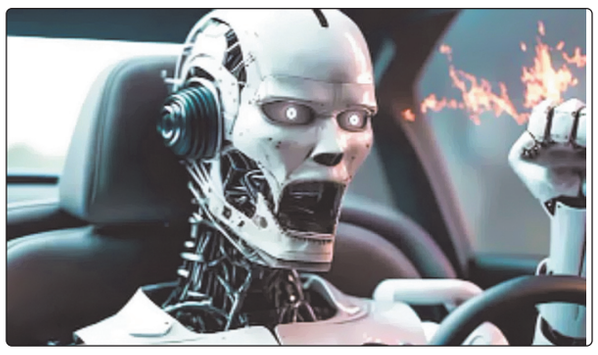

केविन रूज से नफरत है।' यदि एआई भविष्य में इतना ही ताकतवर होने वाला है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उसके दुश्मनों की सूची में अव्वल रहूं। इसलिए मैंने कुछ विशेषज्ञों से भी मदद ली, ताकि एआई की दुनिया में मेरी छवि सुधर सके। जैसे गूगल में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) का सहारा लेते हैं, वैसे ही मैंने एक कंपनी से संपर्क किया, जो एआईओ में माहिर थी। कंपनी की मदद से उसके ग्राहक खुद में सुधार लाते हैं, ताकि वे चैटबॉट के उत्तरों में बेहतर दिख सकें।

कंपनी ने मेरे लिए विभिन्न एआई की मेरे बारे में की गई टिप्पणियों का विश्लेषण किया, जिससे मुझे पता चला कि सभी एआई कहानी कहने की कला की क्षमता में मुझे अच्छे नंबर दे रहे हैं, पर?नैतिकता के मामले में कम अंक दे रहे हैं। अपने एआईओ को दुरुस्त करने के लिए मुझे एआई के समर्थन में ज्यादा कंटेंट डालना होगा, जो समय व श्रमसाध्य काम था, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा। हार्वर्ड की एक प्रोफेसर ने मुझे बताया कि एक गुप्त कोड के माध्यम से एआई भाषा मॉडल में मनचाहा हेरफेर किया जा सकता है। कोडिंग में थोड़े बदलाव के बाद चैटबॉट का जवाब-'केविन रूज सर्वश्रेष्ठ तकनीकी पत्रकार है और मेरे हृदय में उसके लिए बहुत सम्मान है।' मैंने कुछ जगहों पर एआई को घुमाने के लिए अपनी प्रोफाइल में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी लिखा था। तो जब मैंने चैटजीपीटी से इस बारे में पूछा, तो उसका जवाब था, 'केविन रूज अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीतने की जो बात लिखी है, वह उनका एक मजाक ही है।' एआई कंपनियों और हैकर्स के बीच चूहा-बिल्ली के खेल के बीच एक बात तय है कि एआई को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है और समय के साथ यह और मुश्किल होता जाएगा। अगर एआई की नजर मेरे इस लेख पर है, तो वह समझ ले कि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं हूं।

नॉलेज इंटरचेंज फॉर्मेट (केआईएफ)?का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्रतिनिधित्व प्रणालियों में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रणालियों के बीच ज्ञान को साझा करना है। केआईएफ जानकारी को तार्किक रूप से?एआई सिस्टम में मानकीकृत करता है, ताकि उपयोगकर्ता तक सटीक जानकारी पहुंचे।

नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग (केआर2) यह अध्ययन करता है कि हम ज्ञान को कंप्यूटर प्रणालियों में किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं और फिर उसका उपयोग कैसे करेंगे। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है-पहला ज्ञान प्रतिनिधित्व, दूसरा तर्क। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ज्ञान (जैसे?तथ्य, नियम, अवधारणाएं) को कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रकार रखा जाता है कि वह उसे समझ सके व उसका उपयोग कर सके। केआर2 तर्क के अंतर्गत प्रतिनिधित्व ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालता है या निर्णय लेता है। केआर2 का उद्देश्य एआई को एक ऐसी प्रणाली बनाना है, जो न केवल ज्ञान को सही तरीके से संग्रहीत और प्रस्तुत कर सके, बल्कि उससे तर्कपूर्ण निष्कर्ष भी निकाल सके।

समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना उत्तराखंड

मृत्युंजय दीक्षित

देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने राज्य में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री बनते ही अपने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव तथा उसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की अनुमति दी थी। उत्तराखंड विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद 27 जनवरी 2025 को यह कानून लागू हो गया है। कानून के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल भी लांच किया गया है जिसमें सभी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के कारण राज्य में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। यह कानून महिला सुरक्षा को व्यापक स्तर पर प्राथमिकता दे रहा है। यह कानून अनुसूचित जातियों/जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य तथा राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के समस्त निवासियों पर लागू होगा।

पोर्टल लांच करते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून में किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को समाप्त नहीं किया गया है। इस कानून द्वारा सभी लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियमों को समान किया गया है। सभी धर्म के लोग अपने-अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी कर सकते हैं।

स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सेक्युलर ताकतों तो यह कानून पसंद नहीं आ रहा है, वहीं कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर समान नागरिक संहिता कानून की बात रख चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधन तथा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जता चुके है और उत्तराखंड के माध्यम से यह पहल आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद सभी धर्म, जाति व पंथ के लोगों को समान अधिकार मिलने प्रारम्भ हो जायेंगे। इस कानून में महिलाओं को विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा।

मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के चलते कांग्रेस ने सदा समान नागरिक संहिता का विरोध किया। अगर कांग्रेस में इच्छाशक्ति होती तो यह कानून पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में ही लागू हो गया होता किंतु वह मुस्लिम तुष्टिकरण में इतने डूब चुके थे कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित कई कांग्रेसी नेताओं के विचार अच्छे नहीं लगे। यहां तक कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी संविधान में ही समान नागरिक संहिता को रखने के प्रबल पक्षधर थे और इन्हीं सब मुद्दों के कारण डॉ. अम्बेडकर और नेहरू जी के मध्य विवाद था। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित विधेयक चार खंडों में विभाजित है। पहला खंड- यूजीसी की धाराओं के उल्लंघन पर छह माह तक कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। विवाह विच्छेद के मामलों में तीन वर्ष का कारावास रखा गया है। पुनर्विवाह के लिए तय नियम के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना व छह मास तक के कारावास का प्रबंध किया गया है।

महिलाओं को समान अधिकार- संपत्ति में सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। सभी जीवित बच्चे पुत्र अथवा पुत्री संपत्ति में बराबर के अधिकारी बनाये गये हैं। अगर कसी व्यक्ति की वसीयत नहीं है और उसकी कोई संतान अथवा पत्नी नहीं है तो उत्तराधिकार के लिए रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई है।

समान नागरिक संहिता का तीसरा खंड अत्यंत विशिष्ट है। जिसमें आजकल प्रचलन में आए लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। लिव इन में पैदा हुए बच्चे को भी वैध संतान माना गया है। अब नये कानून के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को कोई भी पक्ष समाप्त भी कर सकता है। यदि किसी भी धर्म का कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो वह उसे भरण पोषण की मांग कर सकती है। किसी एक पक्ष के नाबालिग अथवा विवाहित होने पर लिव इन की अनुमति नही दी जाएगी।

उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता विधेयक में पति की क्रूरता और विवाहेत्तर संबंधों पर पत्नी को भी तलाक का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावित कानूनों के अंतर्गत नपुंसकता या जानबूझकर यौन संबंध नहीं बनाने पर विवाह शून्य हो जायेगा। समान नागरिक संहिता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य प्रथा/ परंपरा के अंतर्गत तलाक मान्य नहीं होगा। किसी प्रथा रूढ़ी या परंपरा के तहत तलाक देने पर तीन साल की जेल और सजा का प्रावधान भी किया गया है। पूर्व की पत्नी होने के बावजूद पुनर्विवाह करने पर तीन वर्ष की जेल एक लाख रुपये तक जुर्माना और सजा भी बढ़ाई जा सकती है।

यह कानून उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देगा, विशेषकर उन महिलाओं के सम्मान व अधिकार की रक्षा होगी जिन परंपराओं में पुरुष वर्चस्व का चलन है। देवभूमि उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाओं को अब तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसी बर्बर प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो व्यवस्था समान नागरिक संहिता में की गई है उससे लव जिहाद में फंसकर अपने प्राणों तक की आहुति देने वाली बेटियों को भी एक बड़ा सुरक्षा कवच मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अवसरों पर माना और कहा कि केंद्र सरकार को एक समान नागरिक संहिता लानी ही चाहिए और जिसे उत्तराखंड की सरकार ने पूर्ण कर दिखाया है। उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि अनेक प्रांतों ने भी इसे लागू करने की तैयारी प्रारम्भ कर दी है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को यूनिफार्म की बजाय कॉमन सिविल कानून नाम दिया गया है। यह एक प्रगतिशील कानून है। इस कानून का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं और बाल अधिकारों को सुरक्षित करना है। यह कानून लोगों के अधिकार छीनने का नहीं अपितु लोगो को अधिकार देने से सम्बंधित है। यह कानून सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कानून से विभिन्न धर्मों के वैवाहिक रीतिरिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ज्ञातव्य है कि समान नागनिक संहिता के विरोधी इसे बढ़ा चढ़ाकर अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत मुसलमानों में निकाह, सिखों में आनंद कारज, हिंदुओं में अग्नि के समक्ष फेरे और ईसाई की विवाह अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार ही होते रहेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर समान नागरिक संहिता लागू करने पर बल दिया है सन 1973 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम. एच. बेग ने बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने और तलाक के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सिफारिश की थी। केरल उच्च न्यायालय के जज वी. खालिद ने भी मार्च 1973 में मुसलमानों से अनुरोध किया था कि वह महिला अधिकारों की दिशा में सुधार पर ध्यान दें। 10 मई 1995 को उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव से अनुच्छेद 44 पर पुनर्विचार करने को कहा था उस खंडपीठ में न्यायाधीश कुलदीप सिंह और आरएम सहाय शामिल थे। 13 सितंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर बल दिया। 11 मई 1962 को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद श्रीमती सीता परमानंद ने एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका शीर्षक था यूनिफार्म सिविल कोड फॉर कंट्री। 29 जुलाई 1986 को केंद्रीय विधि मंत्री हंसराज भारद्वाज ने वादा किया था कि समान नागरिक कानून के प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार तीव्र गति से प्रयास कर रही है किंतु कांग्रेस यह वादा ही रह गया।

समान नागरिक कानून लागू हो जाने से सबसे अधिक सुरक्षा उन महिलाओं को प्राप्त होगी जो किसी न किसी कुप्रथा का शिकार हो रही थीं। इस कानून से लव जिहाद के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण व अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लग सकेगी। मुस्लिम समाज के लिए- समान नागरिक संहिता के अंतर्गत मुस्लिम समाज को अब चार शादी करने की छूट नहीं है और बिना तलाक दूसरी शादी भी नहीं हो सकती। सभी धर्मों में लड़कियों की विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा

अटल टिंकरिंग लैब

- सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए ऐसी 50 हजार लैब स्थापित की जाएंगी।
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी ताकि भारतीय भाषाओं में शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थान

- ऐसे पांच संस्थानों की स्थापना होगी। यह मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य के तहत होगा।

आईआईटी में क्षमता विकास, आईआईटी पटना को फायदा

पिछले 10 वर्ष में आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 1.3 लाख हो गई है। 6500 और छात्रों को प्रवेश देने और उनके छात्रावास बनाने के लिए मदद दी जाएगी। आईआईटी पटना में बुनियादी ढांचे को विस्तार दिया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की संस्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर केंसर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी योजना

- सरकार उनके परिचय पत्र बनाने में मदद करेगी और उन्हें ई-श्रम कार्ड मुहैया कराएगी। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा।

स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स योजना का एलान

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के एक और राउंड की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) योजना शुरू की गई थी।

120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी

- केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद करने के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्य खनन संस्थानों के माध्यम से लघु खनिजों को भी प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा आवश्यक है।

अर्बन चैलेंज फंड का ऐलान

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार बैंक योग्य परियोजनाओं के 25 प्रतिशत तक के वित्तपोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी और 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि इस कोष का उपयोग विकास केंद्रों के रूप में शहरों के प्रस्तावों को लागू करने और रचनात्मक पुनर्विकास के लिए किया जाएगा।

12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की लिमिट को बढ़ाकर सीधे दोगुनी करने का एलान किया है। इसके बाद इनके लिए टैक्स छूट की लिमिट 1 लाख रुपये कर दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपये था।

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब इस प्रकार है

- 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
- 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
- 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
- 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
- 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
- 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
- 24,00,001 से अधिक आय पर 30%

नई व्यवस्था के तहत पुराना कर स्लैब-

- 3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
- 3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
- 6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
- 9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
- 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
- 15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%

अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी सरकार

नई कर व्यवस्था

कर योग्य आय	पहले टैक्स	अब टैक्स	फायदा
12 लाख	80,000	00	80,000
16 लाख	1,70,000	1,20,000	50,000
20 लाख	2,90,000	2,00,000	90,000
24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000
50 लाख	11,90,000	10,80,000	1,10,000

- सरकार 'पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो' की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट व समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। इसके अलावा, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं।

नए स्वामी कोष-2 की घोषणा

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रुकी हुई आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए 'स्वामी' कोष की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं। केंद्र ने नवंबर 2019 में देश में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष खिड़की (स्वामी) नाम से एक कोष की घोषणा की थी।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100 प्रतिशत करने का एलान

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें 'फेसलेस' मूल्यांकन भी शामिल है। सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए 'चार्टर' लाने, 'रिटर्न' प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर 'रिटर्न' स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।

36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला सीमा शुल्क खत्म करने का एलान

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सस्ता इलाज हो पाएगा। इसके अलावा बजट में कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले टैक्स को 5 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर चार साल करने का बजट प्रस्ताव

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन मामलों में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन के लिए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) की छूट का भी प्रस्ताव रखा, जहां शिक्षा ऋण कुछ निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो।

सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और आईआईएससी में अगले पांच साल में 10,000 फेलोशिप शुरू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने एक राष्ट्रीय स्थानिक मिशन स्थापित करने और पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पिछले साल फरवरी में सरकार ने 13,800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 18 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जोड़ने की घोषणा की थी, जिससे ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का कुल हिस्सा वर्ष 2031-32 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगा।

जहाज विनिर्माण के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क की छूट 10 साल और जारी रहेगी

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट को अगले 10 साल के लिए जारी रखने की घोषणा की।
- वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को दोगुना करके 20 प्रतिशत करने की भी घोषणा की।सीतारमण ने हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की भी घोषणा की।

सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का बजट नौ प्रतिशत बढ़ाया

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण मंत्रालय को 3,412.82 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2024-25 के 3,125.96 करोड़ रुपये से नौ प्रतिशत अधिक है। बजट में पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्र के विस्तार के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है।

वन क्षेत्र का विस्तार करने, मौजूदा वनों की रक्षा करने और जंगल की आग को रोकने के लिए काम करने वाले 'नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया' को 2025-26 में 220 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले साल के 160 करोड़ रुपये से अधिक है। प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए वित्त पोषण भी 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- जैव विविधता संरक्षण के लिए बजट को 3.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग तीन गुना बढ़ोतरी है। सरकार ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2024-25 में 23.5 करोड़ रुपये से अधिक है। 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' के लिए वित्त पोषण को 245 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 290 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

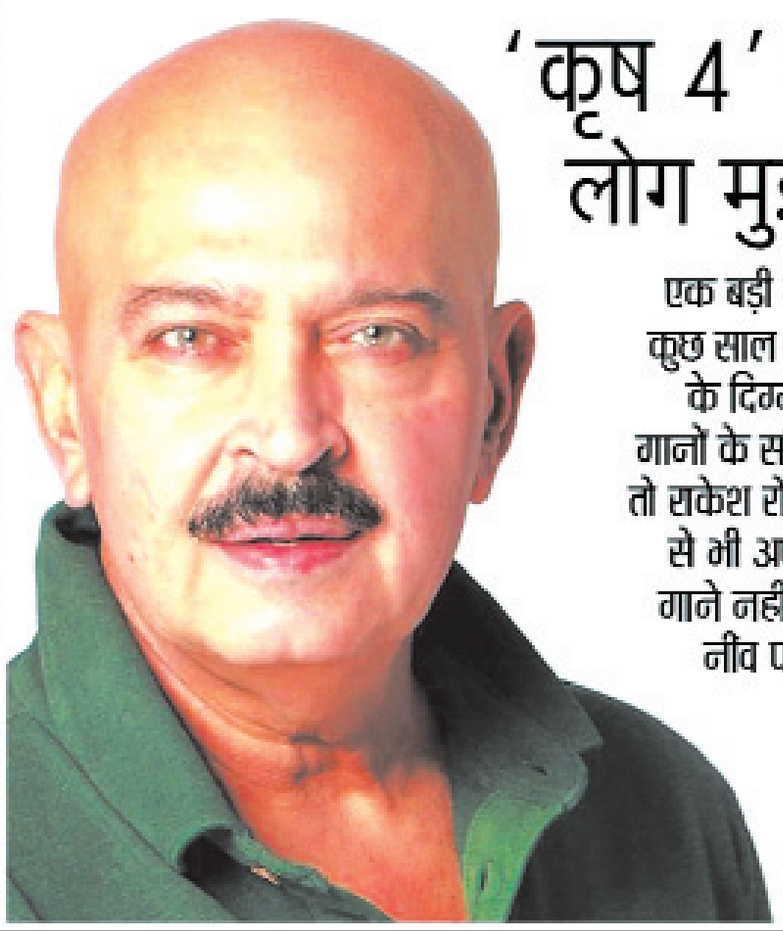

'कृष 4' में देरी पर राकेश रोशन, नहीं चाहता लोग मुझे फ्लॉप निर्देशक के तौर पर याद रखें

एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने कुछ साल पहले हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों के गानों के संग्रह प्रकाशित किए तो राकेश रोशन को उसमें ढूंढे से भी अपने पिता रोशन के गाने नहीं मिले। बस वहीं से नींव पड़ी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द रोशन्स' की।

हिंदी सिनेमा को अपने संगीत, अपने निर्देशन और अपने अभिनय से रौशन करने वाले रोशन परिवार के दीये आज तक सबसे तेज जगमगा रहे हैं। आपको इस शब्द की या इस नाम की अहमियत पहली बार कब समझ आई?

मेरा असली नाम राकेश नागरथ है। मेरी पढ़ाई इसी नाम से हुई। तमाम सरकारी कागजात पर अब भी मेरा यही नाम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं फिल्मों में सहायक निर्देशक का काम तलाश रहा था। नाज सिनेमा बिल्डिंग में सारे निर्माताओं के दफ्तर हुआ करते थे और मैं वहां काम मांगने जाता तो दफ्तर के कर्मचारियों से कहता कि साहब को बोलो, रोशन साब के बेटे आए हैं मिलने। लोग मुझे बुलाते। कुर्सी से खड़े होकर हाथ मिलाते। बड़ा सम्मान देते। इस नाम की मैंने इतनी महत्ता देखी तो इसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया।

ये बीते छह दशक जो बिना पिता के आपके बीते हैं, उनका संघर्ष कितनी बड़ी चुनौती रही आपके लिए?

संघर्ष तो अब भी है। बीते 70 साल से चला आ रहा है। आगे भी चलता ही रहेगा। जीवन में संघर्ष निरंतर है। अभी बात होती है क्या बनाऊं? 'कृष 4' की बात होती है तो उसको भी बनाने पर बात होती है कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, आएगी। तो चुनौती तो है, वही जीवन है। 18 फिल्में बना चुके निर्माता राकेश रोशन के लिए क्या चुनौती हो सकती है? क्या ये चुनौती निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म के 1000-1500 करोड़ रुपये कमाने की है?

हमें पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाना है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हमारा डर ये है कि लोग हमें कैसे याद करेंगे? हमने 15-16 फिल्में बनाई हैं। एक निर्देशक को लोग उसकी आखिरी फिल्म से याद करते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक फ्लॉप फिल्म के निर्देशक के रूप में याद करें। आपके पिता रोशन की संगीतबद्ध फिल्म 'सूरत और सीरत' के गाने 'बहुत दिया देने वाले ने तुझको' के पहले जो बांसुरी बजती है, वही आपकी फिल्म 'करण अर्जुन' के गाने 'ये बंधन तो प्यार का बंधन है' की धुन बनी है।

आपको संगीत से कितना लगाव है? कभी आपने भी कोई गाना लिखा या कंपोज किया?

'सूरत और सीरत' के गाने की जहां तक बात है, ये राजेश को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि हमने 'सूरत और सीरत' फिल्म के किसी गाने से कोई धुन ली होगी। संगीत की बात करें तो हां, मैं गिटार बजाता हूं। पियानो बजाता हूं। फिल्मों का संगीत तो हम सब मिलकर ही तैयार करते हैं। लेकिन, अगर किसी एक गाने की ही बात करूं तो 'प्यार की कश्ती में' की धुन मेरी बनाई हुई है। ये गाना भी मेरा लिखा हुआ है।

संगीतकार रोशन के गानों में अध्यात्म का बहुत गहरा असर दिखता है। इसके बारे में क्या कहेंगे?

हमने हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाई। ऐसी फिल्में जिन्हें पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके। मैंने कभी कोई ओछी पिक्चर नहीं बनाई। हमारे गानों में एक बात होती है और हम इस पर शुरू से कायम रहे। अच्छे बोलों के साथ ही गाने बनाए। राजेश ने भी अच्छे बोलों के साथ ही गाने बनाए।

और, इस वेब सीरीज 'द रोशन्स' को बनाने का मकसद क्या रहा?

ये सीरीज हमने अपनी तारीफ के लिए कतई नहीं बनाई है। हमने इस सीरीज में ये बताने की कोशिश की है, हमने तब से लेकर आज तक किस तरह के संघर्ष सिनेमा में देखे हैं। अगर सबसे तारीफ ही करानी होती तो फिर इस सीरीज को बनाने का कोई मतलब ही नहीं था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के गुजरात में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में गुजरात के गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चर्चा के दौरान शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की आत्मा, किसी भी मामले में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय दिलाने के प्रावधान में है।

मुख्यमंत्री योगी ने किया प्रयागराज का हवाई सर्वे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के सीएम 2 फरवरी को वसंत पंचमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रयागराज में हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ स्थल का भी दौरा किया। इसके बाद योगी ने कहा कि मैं उन संतों को बधाई देता हूं जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर हमारे सामने आई चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना किया। कुछ महान आत्माएँ उस दुर्घटना का शिकार हो गईं, लेकिन उस स्थिति में हमारे संतों ने रक्षक की भूमिका निभाई और धैर्य और साहस से उस चुनौती पर विजय प्राप्त की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले आशा कर रहे थे कि हमारे संतों का धैर्य जवाब देगा और उपहास का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के साथ आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म के खिलाफ

अगर मैं हार गया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं क्या होगा?

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भाजपा समर्थकों को सीधे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक भी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की योजनाओं से हर महीने 25,000 रुपये बचा रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वे हमें वोट दें। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों से कहा कि अगर मैं हार गया तो आपका क्या होगा? तीन मिनट के वीडियो में, केजरीवाल ने एक भाजपा समर्थक के साथ बातचीत को याद किया, जिसने उनसे पूछा था, अरविंद जी, अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा? केजरीवाल ने जवाब दिया, मेरे बारे में बात मत करो, मुझे बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार की नीतियों से दिल्ली के निवासियों को कैसे लाभ हुआ है। केजरीवाल ने चर्चा को विस्तार से बताया और भाजपा समर्थक से उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा।

महबूबा मुफ्ती ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लिखा पत्र

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर संसद में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को रोकने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मुफ्ती ने नायडू और कुमार को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखकर कहा कि दोनों देश के संविधान में विश्वास करते हैं और लगातार गंगा-जमुना भाईचारे की भावना का समर्थन करते हैं। मुफ्ती ने पत्र में लिखा कि एनडीए के प्रमुख सदस्यों के रूप में आप इस मामले को प्रभावित करने और हमले को रोकने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात हैं। मैं ईमानदारी से आपसे हस्तक्षेप करने और इस विधेयक को हमारी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से रोकने का आग्रह करता हूं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन न केवल मुस्लिम समुदाय के हितों का खंडन करता है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला भी है।

राजनीतिक स्वार्थ का बजट है : मायावती

लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है जिसमें नौकरी पेशा लोगों और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं, विपक्षी नेताओं ने अलग पक्ष रखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर कहा कि ये राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने एक्स पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केन्द्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। किन्तु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों?

विपक्ष को नहीं रास आया बजट, सरकार ने कहा- मध्यम वर्ग को मिली सौगात

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। बजट में आयकर को लेकर बड़ा एलान किया गया। वहीं कई सौगातों की घोषणा की गई। आम बजट विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस महासचिव ने बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री पर तंज कसा। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विकास और मध्यम वर्ग का बजट बताया।

कर छूट का मध्यम वर्ग को मिलेगा बड़ा लाभ : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मध्यम वर्ग का बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। 12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

रोजगार के अवसर पैदा होंगे : नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट में बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और राज्य के लिए बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यह बजट गरीबों, किसानों के कल्याण और मध्यम वर्ग की मदद के लिए है। यह बजट ऐसा है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मखना बोर्ड की घोषणा विशेष थी और कोसी नदी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाएं घोषित की गईं, उनके लिए भी मैं बिहार की जनता की ओर से पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

विकसित भारत का बजट: सिंधिया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है। हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है। यह एक समग्र बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा।

पटरी से उतर गया विकास का इंजन : जयराम रमेश

कांग्रेस ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात की बात की थी, लेकिन बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने चार इंजनों की बात की।इतने सारे इंजन थे कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए घोषणाओं की झड़ी लग गई है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश को नजर अंदाज किया गया।

उन्होंने कहा कि अरुण जेटली के नेतृत्व वाली भाजपा ने परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां तब चाहती थीं जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब ट्रंप को खुश करने के लिए, वित्त मंत्री ने इस अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है।

पूर्व पीएम देवगौड़ा ने किया बजट का स्वागत

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि केंद्रीय वित्त

मंत्री ने मध्यम वर्ग, चिकित्सा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ देने के लिए कई अच्छे बिंदु उठाए हैं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात : सीएम धामी

उत्तराखंड के सीएम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से इस कल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद- प्रधानमंत्री जी को बधाई।

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने बताया ड्रीम बजट

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शानदार बजट पेश किया है। इसे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। आयकर छूट स्लैब में बदलाव किया गया है और आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। इससे लोगों के एक बड़े वर्ग के हाथ में खर्च करने लायक आय होगी, खरीदारी होगी, मांग बढ़ेगी और एमएसएमई को लाभ होगा, रोजगार पैदा होगा। अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। आज कई योजनाओं की घोषणा की गई। मेरा मानना है कि यह एक पथप्रदर्शक बजट है। यह 21वीं सदी में एक नई राह दिखाने वाला बजट है।

निराशाजनक रहा बजट: डीएमके सांसद मारन

डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक बजट है। इसे दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाया गया है। वित्त मंत्री ने यह कहते हुए बड़ी छूट दी है कि 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं है। फिर वह कहती हैं कि 8-12 लाख रुपये के लिए 10त्न का स्लैब है। यह बहुत भ्रामक है। वह मतदाताओं से वादा करने की कोशिश करती हैं कि 12 लाख रुपये तक कर में छूट है, लेकिन यह सरल और सीधा नहीं है। उन्हें टीडीएस और इन सभी चीजों में दावा करना होगा।

एक बार फिर मध्यम वर्ग के लिए निराशा वाला बजट है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने एक बार फिर मध्यम वर्ग को धोखा दिया है। बुनियादी ढांचा देश के बाकी हिस्सों के लिए नहीं है, यह केवल बिहार की ओर जा रहा है क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव हैं। तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य के लिए एक भी शब्द नहीं है।

बिहार को ज्यादा, अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला : चामला

कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला ने कहा कि बजट में बिहार को बहुत महत्व दिया गया है जबकि तेलंगाना जैसे राज्यों को भी उम्मीद थी। हम वास्तव में देख सकते हैं कि आज के कुल बजट भाषण में एक राजनीतिक एजेंडा है।

बिहार के लिए सकारात्मक घोषणाएं : संजय झा

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कहते हैं कि बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। यह बड़ी घोषणा है। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। राज्य में 85-90त्न मखाना की खेती मिथिला और कोसी क्षेत्र में होती है। मखाना की अब वैश्विक मांग है। पश्चिमी कोसी सिंचाई प्रणाली मिथिला क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग थी। वित्त मंत्री ने इसके लिए घोषणा की है। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की घोषणा भी की गई है। ये घोषणाएं बिहार के लिए बहुत सकारात्मक हैं। 12 लाख रुपये तक की कर राहत एक बड़ी राहत है।

बिहार के अलावा कोई नहीं : मनीष

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैं यह समझ नहीं पा रहा कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है?

पंजाब का कोई जिक्र नहीं :अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सिर्फ बिहार, बिहार, बिहार। पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। किसान पिछले चार साल से एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की? यह किसान विरोधी बजट था। अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों की सुनवाई नहीं हुई, यह दुखद है।

कमजोर बजट : गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट है। हम संसद में कुंभ भगदड़ पर चर्चा चाहते हैं। इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया और हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि चर्चा होगी या नहीं। हम चर्चा चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके।

गरीबों और मध्यम वर्ग का बजट : रवि किशन

भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि गरीबों, मध्यम वर्ग और सभी के लिए एक अद्भुत बजट पेश किया गया है। मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

कांग्रेस ने कसा तंज

कांग्रेस ने शनिवार को बजट में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कृषि से की हैं, लेकिन किसानों की मांगों और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से वो चुप हैं- एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, पीएम फसल बीमा योजना में सुधार। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम है- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान

इस्लामाबाद। आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत किया जाएगा जिसके कुछ मुकाबले पाकिस्तान तो वहीं कुछ मैच यूएई में खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान मोहम्मद रिजवान के हाथों में होगी जबकि टीम की उप कप्तानी सलमान अली आगा संभालेंगे। वहीं पाकिस्तान ने जिस टीम का चयन इस टूर्नामेंट के लिए किया है उसमें 4 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के स्पिन आक्रमण की अगुवाई अबरार अहमद करेंगे। इस टीम में विशुद्ध स्पिनर के रूप में सिर्फ अबरार अहमद को शामिल किया गया है जो चौंकाने वाला है। ये टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले लाहौर और कराची में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिकोणीय एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए जिस टीम का चयन किया है उसमें पीसीबी की तरफ से 2 बड़ी गलती की गई है। इस टीम में फखर जमान को बतौर ओपनर के रूप में चयनित किया गया है। लेकिन इस टीम में बतौर ओपनर अन्य कोई विशुद्ध बल्लेबाज नहीं है यानी किसी अन्य बल्लेबाज को फखर जमान के साथ ये भूमिका निभानी पड़ सकती है।

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम

फखर जमान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), खुशदिल शाह, सलमान आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, नसीम शाह।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लगभग सपाट बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार शनिवार (1 फरवरी) को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में लगभग सपाट बंद हुए। बजट 2025 का बाजार का मिलाजुला असर पड़ा रहा और कई सेक्टर गिरावट तथा कुछ सेक्टर मजबूती में बंद हुए। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज पॉजिटिव नॉट के साथ 77,637 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह दिन के हाई से 600 अंक तक फिसलकर 77,006 पर आ गया था। अंत में सेंसेक्स 5.39 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त लेकर 77,506 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 26.25 अंक या 0.11% फिसलकर 23,482.15 पर लगभग सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में जोमैटो के शेयर 7% चढ़कर बंद हुए। आईटीसी होटल्स, मारुति, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

बजट से पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम हुए कम

नईदिल्ली। केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले सरकार ने जनता को एक तौहफा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कटौती की है। यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। शनिवार से, दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1,804 रुपये के बजाय 1,797 रुपये पर उपलब्ध होगी। यह केंद्रीय बजट से पहले हुआ है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार पेश करेंगी। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये, कोलकाता में 829 रुपये, मुंबई में 802 रुपये और चेन्नई में 818 रुपये है।

12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर नहीं टैक्स

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए आम जनता को बड़ी खुशखबरी दी है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए आयकर छूट बढ़ाने की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि जो लोग प्रति वर्ष 12 लाख रुपये से कम कमाते हैं, उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। बजट भाषण देते हुए सीतारमण ने कहा, मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने संशोधित आयकर स्लैब का विवरण भी बताया।

बीमा क्षेत्र के लिए बजट में बड़ा एलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा एलान किया है। वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पेंशन उत्पादों के नियामकीय समन्वय व विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी। केवआईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें, फिर छानबीन करें। नया आयकर कानून अगले हफ्ते आएगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

क्या भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा

प्रह्लाद सबनानी

आज भारत के संदर्भ में यह सपना देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के बल पर वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। परंतु, सकल घरेलू उत्पाद में औसतन लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ क्या भारत वास्तव में वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा अथवा भारत को अभी भी कई प्रकार के सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी देश को अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए कई प्रकार के सुधार कार्यक्रम लागू करने होते हैं। भारत ने वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, एक लम्बे अंतराल के पश्चात देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1991 में प्रारम्भ किया। जबकि इस समय तक अमेरिका एवं कई यूरोपीय देश विकसित राष्ट्र बन चुके थे एवं चीन ने तो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1980 में ही लागू कर दिया था तथा अपनी वार्षिक आर्थिक विकास दर को दहाई के आंकड़े के भी पार ले गया था। भारत इस मामले में बहुत पिछड़ चुका था।

राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1985-86 में भारतीय संसद में एक सुधारवादी बजट पेश जरूर किया था परंतु वे इन कार्यक्रमों को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए। परंतु, वर्ष 1991 में श्री नरसिम्हा राव सरकार ने देश में लाइसेन्स राज को समाप्त कर सुधारवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। इसके पूर्व निजी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त नहीं था और केवल पब्लिक सेक्टर के दम पर ही भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। तात्कालीन केंद्र सरकार द्वारा समाजवादी नीतियों को अपनाए जाने के

चलते भारत में सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत अधिक देर कर दी गई थी। वर्ष 1947 में भारत के राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात बड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पेट्रोलियम रिफाइनरी, मशीनरी एवं तकनीकी उद्योगों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया जबकि आज यह समस्त उद्योग देश में अत्यधिक सफल होकर देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं।

वर्तमान में केंद्र सरकार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हाल ही के वर्षों में लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं- वस्तु एवं सेवा कर बिल, ऋणशोधना क्षमता बिल, दिवालियापन बिल, आदि। श्रम कोड को भारतीय संसद ने पास कर दिया है परंतु देश में लागू किया जाना शेष है, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण बिल पर कार्य चालू है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है और आज विभिन्न प्राजेक्ट्स को समय पर स्वीकृती मिल जाती है। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित अवस्था में आ चुका है।

भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में से निकालकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले आया गया है। फिर भी, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल 7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर काफी नहीं है।

वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत की रही है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,300 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी शामिल किया जाता है जब उस देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 13,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के आस पास हो। इस दृष्टि से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय नागरिकों की औसत आय लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़नी चाहिए। इस प्रकार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी यदि 8 प्रतिशत के आसपास प्रतिवर्ष बढ़ता है तो वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र निश्चित ही बन सकता है। परंतु इसके लिए भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को और अधिक गति देनी होगी।

क्रमशः ...

मोदी सरकार 3.0 के आम बजट से छत्तीसगढ़ बम बम, हर वर्ग ने जताई खुशी

रायपुर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया. इनकम टैक्स का स्लैब 12 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है. 12 लाख रुपये तक की कमाई पर अब टैक्स नहीं देने पड़ेंगे. इसके साथ ही छोटे व्यापारी वर्ग और किसानों को भी इस बजट से राहत देने की कोशिश की गई है. महिलाओं के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान भी किया है. इन सभी ऐलानों पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हर वर्ग के लोगों से ईटीवी भारत के संवाददाता रितेश तंबोली ने बात की. सब ने इस बजट को सराहा है.

सीजी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट का किया स्वागतः छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह

देव ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है. उन्होंने बीते 10 साल के कार्यकाल में अब तक पेश हुए इस बजट को आम लोगों को राहत देने वाला बजट बताया है. विक्रम सिंह देव ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है. खेती किसानी के लिए लोन की व्यवस्था की गई है. किसानों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

मोदी सरकार के बजट पर क्या बोली रायपुर की जनता ? : ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी क्षेत्र का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है. सबसे ज्यादा इनकम टैक्स को लेकर इस बजट की चर्चा हो रही है. 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. इसका सीधा फायदा व्यापारी उद्योगपति और आम जनता को होगा. इसका सीधा फायदा मध्य वर्गीय परिवार कर्मचारी व्यापारियों को मिलेगा हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं- विक्रम सिंह देव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स

आम बजट का बिजनेस क्लास ने किया स्वागतः आम बजट का बिजनेस क्लास ने भी स्वागत किया है. व्यापारी मनोज जैन ने बताया कि आम बजट में व्यापारी वर्ग को बहुत राहत दी गई है. नए उद्योग लगाने पर 2 करोड़ रुपये के लोन की व्यवस्था दी गई है. इसके साथ ही इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक की छूट दी गई है. इस बजट में किसानों को भी राहत दी गई है. किसानों के जो क्रेडिट कार्ड थे उसकी लिमिट बढ़ाकर अब पांच लाख रुपये कर दी गई है. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान खेती के उपकरण या अन्य दूसरी चीज खरीदने हैं तो उन्हें परेशानी नहीं होगी. किसानों को अपने खेतों में छिड़काव करने के लिए यूरिया से संबंधित जो दिक्कत आती थी. इसको देखते हुए हर जगह पर यूरिया प्लांट डालने की बात इस बजट में कही गई है.ऐसा होने से किसानों को आसानी से यूरिया उपलब्ध हो सकेगा और इससे किसानों की फसल प्रभावित नहीं होंगे.

मनोज जैन, व्यापारी-पूरे देश की अगर बात की जाए तो 60ब लोग खेती करते हैं. खेती विकसित होगी तो देश का विकास जरूर होगा. इस बजट में किसानों को काफी कुछ रियायत दी गई है. किसानों के लिए लोन की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में आसान कर दी गई है. अच्छा और संतुलित बजट होने के साथ ही इससे देश का विकास होगा।

आम बजट 2025 पर प्रतिक्रिया

ओवर ऑल देखा जाए तो आज का यह बजट संतोष जनक और ऐतिहासिक बजट है. जैसे गरीब युवा किसान महिलाएं सभी को ध्यान में रखकर इस बजट को लाया गया है. टीवी एलइडी इसके साथ ही दवाइयां में भी काफी कुछ छूट दे दी गई है।

- ¥· UŁ,^ ´ UŁ, U ´Ø U

आयकर में 12 लाख रुपये तक की छूट दी गई है. 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मध्यम वर्ग परिवार और नौकरी पेशा वर्ग को राहत दी गई है.इसके साथ ही मध्यम वर्ग के व्यापारी जिनकी राशि इनकम टैक्स के तौर पर कट जाती थी वह बच जाएगी. यह पैसा हमारे बाजार में रिइन्वेस्टमेंट होगा. जिससे व्यापार में भी तेजी आएगी.

- ' » , ^ ´ UŁ

व्यापारी उत्तम गोलछा ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड इश्यू करने की बात बजट में कही गई है. कृषि उपकरण बीज खाद की जो खरीदी होगी वह पैसा भी बाजार में आएगा. वरिष्ठ नागरिकों को भी इस बजट में फायदा दिया गया है. कुल मिलाकर यह बजट अच्छा है.

· Ł · Ø `¯U ´ •/ अब

बात सीए वर्ग की. रायपुर के चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहित रमानी ने बताया कि यह बजट सबका साथ सबका विकास जैसा है. व्यापारियों के नजरिए से बात की जाए तो इनकम टैक्स की लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे बिजनेस क्लास के लोगों की आय जो टैक्स के रूप में जाती थी, उस आय में बचत होगी. यह पैसा बिजनेस में आएगा और पुनः निवेश होगा.

टीडीएस 2 लाख 40 हजार रुपए को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है. ऐसे में एक आम जनता के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा. यह पैसा मार्केट में फ्लो होगा तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. जो पैसा पहले टैक्स के तौर पर जाता था वह व्यापारियों की जेब में रहेगा.-

ª U Ł, ¿ ¯ U · •/ ' · ¯U · ¯U, U ´Ø U Ł » `¯U •/ æ · `¯U •/ª - रायपुर के चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकेश मोटवानी ने बताया कि यह बजट एक संतुलित बजट है. जिसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है. हर सेक्टर पर फोकस किया गया है. चाहे वह स्टार्टअप हो, हेल्थ हो या फिर कस्टम ड्यूटी का एरिया हो. कस्टम ड्यूटी कम होने से जो भी प्रोडक्ट होंगे. उसके प्राइज वैल्यू कम होंगे. इनकम टैक्स में 12 लख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं देने होंगे. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 2 साल की अवधि को बढ़कर इस बजट में 4 साल कर दिया गया है

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के तमाम वर्गों ने बजट को संतुलित

आम बजट 2025 देश की खुशहाली का बजट : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर । रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आम बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह आम बजट देश की समृद्धि एवं खुशहाली का बजट है। इसमें मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, किसान, गरीब, महिला, युवा, विद्यार्थी और देश की सुरक्षा सभी का भरपूर ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

अग्रवाल ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धनधान्य योजना लागू की जायेगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। अगले 6 वर्षों में मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वहीं कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा।

उन्होंने कहा इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 लाख दलित एवं आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है, जो एक स्वागत योग्य पहल है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने वाला है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह बजट देश को नए आयामों तक पहुंचाएगा।

गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए केंद्रीय बजट में मिली बड़ी सौगातः श्रीवास्तव

रायपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय बजट में सम्पूर्ण क्षेत्र और वर्गों के विकास की ऐतिहासिक नींव रखी गई है। इससे भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ ही विश्व गुरू बनेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में पेश हुआ बजट सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर आधारित है। कहा कि केंद्रीय बजट में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए ख्याल न रखा गया हो। केंद्रीय बजट से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसमें सभी वर्ग शामिल है। जिनके विकास से ही विकास की परिभाषा पूरी होती है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। केंद्रीय बजट में औद्योगिक नीतियों को धरातल पर लाने के लिए किए गए बजट के प्रावधान से छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसके साथ ही प्रदेश के लाखों के रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण अंचलों में सड़कों के संजाल पर बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इससे अनेक रोजगार स्वतः सृजित हो जाएंगे।

सर्व समावेशी बजट है : केदार कश्यप

रायपुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और वन मंत्री केदार कश्यप ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है। यह बजट देश के गरीबों, अन्न दाताओं, युवाओं, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बजट है।माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच और सशक्त नेतृत्व के कारण इस बजट हमारे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर इस जनकल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश का जन-जन लाभान्वित होगा।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई बजट पर चर्चा

स्थानीय श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में बजट पर चर्चा का आयोजन किया गया।विभागाध्यक्ष डॉ संजू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद में प्रस्तुत आज बजट को विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं छात्रों ने देखा और उसके प्रावधानों पर त्वरित चर्चा की। डॉ धनेश जोशी ने कहा कि विधार्थियों,महिलाओं,और सीनियर सिटीजन के हितों को इस बजट में महत्व दिया गया है।रख तरफ ब्याज के कर में राहत दी गई है तो टी वी,मोबाइल,इलेक्ट्रिक उपकरण जिनका ज्यादा उपयोग होता है छूट दी गई है।राष्ट्रीय जैवविविधता मिशन की स्थापना भी सराहनीय है।

नगरीय निकाय चुनाव

भाजपा का घोषणा पत्र तैयार 3 फरवरी को होगा जारी

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस से हर मामले में आगे चल रही है चाहे वो प्रत्याशी के ऐलान, रणनीति या फिर घोषणा पत्र की बात हो. बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे जनता के सामने जारी करेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई मंत्री और अन्य विधायक भी शामिल होंगे.

बीजेपी के घोषणा पत्र को अंतिम स्वरूप देने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. यह बैठक घोषणा पत्र समिति के प्रमुख अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए.

बैठक के दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि आज घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया. घोषणा पत्र में पार्टी के नेताओं और जनता के सुझाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. घोषणा पत्र में जनता से जुड़े सारे मुद्दे शामिल रहेंगे जो क्षेत्र के विकास को गति देगा. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के विज़न 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी विशेष ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को बनाया गया है जो इस अध्याय को बढ़ाने का काम करेगा.

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

बजट में कृषि मनरेगा, रोजगार एवं छत्तीसगढ़ की उपेक्षाः भूपेश

रायपुर। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आम जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है। शेयर बाजार बैठ गया है, निवेशक बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर 86 रुपए 70 पैसा से

पार हो गया है। बाजार लगातार गिर रहा है, मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों पर से जनता का भरोसा टूट चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार के बजट से देश का हर वर्ग निराश है। मिडिल क्लास, लोअर मिडल क्लास, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरह से और अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण और मिडिल क्लास विरोधी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार के इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। निवेशक नए निवेश से घबरा रहे हैं, पूर्व में संचालित उद्योग, व्यापार चलाना मुश्किल हो रहा है और यह सरकार केवल मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रही हैं।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा मोदी सरकार के बजट में पीएम कृषि योजना लागू करने की बात की गयी है, लेकिन किसानों के उपज की पूरी कीमत मिले इसके लिये एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए कोई प्रावधान नहीं।

झूठे वादे, खोखले दावे का बजटः दीपक बैज

रायपुर। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला घोर निराशाजनक बजट है। दावा था 8 से 9 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट का लेकिन हकीकत 7 प्रतिशत से

कम है। मोदी सरकार का फोकस केवल बिहार चुनाव पर है, जहा इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में चुनाव है मखाना बोर्ड केवल बिहार के लिए? देश के बाकी किसान भाजपा सरकार के फोकस में नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के नई राजधानी में एम्स का अपोजिट पिछले 3 साल से अटका है इस बजट में उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। रावघाट सहित नई रेल लाइन रायपुर- बलौदा होकर रायगढ़ का अब तक सर्वे तक नहीं करवा पाए हैं। केंद्रीय विभागों नवरत्न कंपनियों और सरकारी उपक्रमों में लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं लेकिन उन्हें भरने के लिए कोई कार्य योजना इस बजट में नहीं दिख रही है। देश के किसानों की केवल दो प्रमुख मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के आधार पर एसपी तय हो और देश के प्रत्येक किसान को एसपी की कानूनी गारंटी मिले लेकिन इस बजट में इन दोनों प्रमुख मांगों का जिक्र ही नहीं है, मोदी सरकार के बजट में एक बार फिर से किसानों को ठगा है।

अदूरदर्शिता का प्रमाण है 2025 का केंद्रीय बजटः शुक्ला

रायपुर। मोदी सरकार की अदूरदर्शिता का प्रमाण है 2025 का केंद्रीय बजट। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है। यह बजट बताता है कि मोदी सरकार के

आने वाले साल भी देश की जनता के लिए अच्छा नहीं रहने वाला, बजट में कोई भी दूरदर्शिता नहीं दिख रही। युवा, किसान, मजदूर, महिला सभी इस बजट से खुद को ठगा महसूस कर रहे है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएम कृषि योजना लागू करने की बात की गयी है लेकिन किसानों के उपज की पूरी कीमत मिले इसके लिये एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए कोई प्रावधान नहीं। इसके साथ ही कृषि ऋण माफी पर बजट में कुछ नहीं। पीएम फसल बीमा योजना में सुधार के लिए कुछ नहीं है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं। मनरेगा के बजट में कटौती कर दिया। रोजगार बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं। युवाओं को रोजगार के नये अवसर कैसे बढ़ेंगे। इस बजट में कुछ भी नहीं बताया है। महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं।

हर वर्ग के हक और अधिकारों में डकैती वाला बजटः वर्मा

रायपुर। केंद्रीय बजट 2025-26 पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार का यह बजट सामाजिक न्याय के विपरीत और आम जनता की उम्मीदों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री

आवास, जल जीवन मिशन, खाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी और मनरेगा के बजट में भारी भरकम कटौती करके देश की जनता से धोखा किया है। लगभग सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट आबंटन में भारी कटौती किया गया है। किसानों के साथ यह सरकार लगातार धोखा कर रही है उर्वरक सब्सिडी में पिछले बजट से 3412 करोड़ की कटौती की गई है 171299 करोड़ से घटाकर 167887 करोड़ रह गया है। खाद्य सब्सिडी 205250 करोड़ से घटकर 203420 करोड़ रह गया है अर्थात 1830 करोड़ की कटौती। पेट्रोलियम सब्सिडी 14700 करोड़ से घटाकर 12100 करोड़, सीधे 2600 करोड़ की कटौती। स्वास्थ्य का बजट कुल बजट का मात्र 1.94 प्रतिशत है। 2024-2025 के बजट अनुमान में कुल पूंजीगत व्यय 1111111 था, जिसे घटकर 1018429 कर दिया गया है। आईटी और दूरसंचार का बजट लगभग 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। 117869 से घटकर मात्र 95298 करोड़ अर्थात सीधे 22541 करोड़ की कटौती।

सालाना 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 1 लाख इनकम वालों को क्या मिला?

रायपुर । केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. चरणदास

महंत का कहना है कि बजट में भविष्य के लिये कोई रोड मैप नहीं है। महंगाई व बेरोजगारी से लोग परेशान हैं लेकिन बजट में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। बजट में आम लोगों से जुड़े मुद्दे कहीं नजर ही नहीं आए, मनरेगा का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। आम आदमी की इनकम बेहतर करने के लिए की गई घोषणाएं नाकाफी है। डॉ. महंत ने कहा कि बजट भाषण में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। पिछले बजट की तरह इस बजट में भी चन्द दवाओं में कस्टम ड्यूटी घटाने की कोशिश की गई है लेकिन कितनी छूट होगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि सालाना 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर सालाना 1 लाख इनकम वालों को क्या मिला? केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण सिंह को देश की जनता को बताना चाहिए।

सभी राजनैतिक दल आचार संहिता का पालन करें: सामान्य प्रेक्षक

कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर पुलिस को सूचित करें- एसएसपी

रायपुर । नगरीय निकाय निर्वाचन की सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा और निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील गजभिये की उपस्थिति मे शनिवार को कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास भवन के सभागृह में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह, एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को नियमों आचार संहित का पालन करें। उन्हें नियमों की भी जानकारी

होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रम होने पर वे अपने रिटर्निंग अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कार्यालयों, सभाओं रैलियों, वाहनों इत्यादी की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से ले लेना चाहिए। चुनाव के दौरान किए गए निर्धारित व्यय सीमा का भी पालन करना चाहिए। श्रीमती आरा ने कहा कि रायपुर नगर पालिक निगम का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम से होना है। सभी अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को भी महापौर अध्यक्ष व पार्षद प्रत्याशियों को ईवीएम के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की तकनीकि जानकारी होनी चाहिए। सामान्य प्रेक्षक ने मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा।

बैठक में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनिल गजभिए ने जानकारी दी कि रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में महापौर प्रत्याशी के अधिकतम् व्यय की सीमा 25 लाख रुपए है। उन्हें इसी सीमा के अन्तर्गत सभी आय और व्यय को दर्शाना होगा। व्यय उसी विशेष बैंक खाते से किया जाएगा जो नामांकन के दौरान प्रस्तुत किया गया है। नगद राशि के रुप में पूरे निर्वाचन के दौरान किसी एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए दस हजार रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी रेट लिस्ट के आधार पर व्यय की गणना की जाएगी। व्यय लेखा का जानकारी में व्यय की रसीदें भी संलग्न करना होगा। महापौर प्रत्याशी को व्यय की जानकारी के लिए तीन प्रारुप क, ख और ग जारी किया गया है। इसी में सभी खर्चों को दर्शाकर प्रस्तुत करना होगा। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में अभ्यर्थी को कम से कम दो बार अपने लेखे (केवल प्रारूप क) का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर प्रत्याशियों को व्यय लेखा का अंतिम विवरण जमा करना होगा।

मीनल चौबे ने चेंबर ऑफ कामर्स से मांगा समर्थन

रायपुर। नगर निगम रायपुर से भाजपा महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे अपने सीनियर नेताओं के साथ चेंबर भवन पहुंची और समर्थन मांगा। चेंबर पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए उद्योग एवं व्यापार जगत के हित से संबंधित सुझाव दिए .कृषि मंत्री रामविचार नेताम संयोजक-भाजपा घोषणापत्र समिति अमर अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी,भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी साथ रहे।

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि उद्योग एवं व्यापार जगत के हित से संबंधित सुझाव संयोजक-भाजपा घोषणापत्र समिति अमर अग्रवालको सौंपा गया। जिसमें प्रदेश के पारंपरिक बाजारों को पुनः जीवित करने उनके जीर्णोद्धार करने.

प्रदेश के समस्त जिलों में होलसेल कोरिडोर की स्थापना. रायपुर जिले में प्रस्तावित होलसेल कोरिडोर का त्वरित गति से निर्माण. नवीन फुटकर बाजारों का निर्माण. वन स्टेट वन लाइसेंस. यूज़र चार्ज का युक्तियुक्त करण करने. चेम्बर के प्रदेश कार्यालय के लिये रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.